VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: एक समीक्षा

डॉक्यूमेंट के बारे में

"भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा" आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला भारत का आर्थिक समीक्षा डॉक्यूमेंट नहीं है। इस साल का आर्थिक समीक्षा डॉक्यूमेंट आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आएगा। वर्तमान डॉक्यूमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले दस वर्षों में इसकी यात्रा का एक विवरण दिया गया है। साथ ही, इसमें आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

"भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: एक समीक्षा" डॉक्यूमेंट के मुख्य भाग में, हमने मूल डॉक्यूमेंट के समान प्रारूप को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बिंदुओं और महत्वपूर्ण डेटा का सारांश दिया है। इसके अलावा, हमने पिछले दशक की निर्णायक नीतिगत कार्रवाइयों पर भी चर्चा की है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app

DELHI: 20 फरवरी, **1 PM** | **BHOPAL: 21** फरवरी

LUCKNOW: 21 फरवरी | **JODHPUR: 21** फरवरी | **JAIPUR: 21** फरवरी

ENGLISH MEDIUM
15 FEB | 5 PM

हिन्दी माध्यम
23 FEB | 5 PM

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स 2024 के लिए मात्र 60 घंटे में

विषय-सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था: अतीत, वर्तमान और भविष्य (Indian Economy: Past, Present and Future) 3
1.1. भूमिका (Introduction) 3
1.2. भारतीय अर्थव्यवस्था और संवृद्धि का कालक्रम {The Indian Growth Story (1950 To 2014)} 3
1.3. 2014 तक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की यात्रा के अनुभव से लिए गए सबक (Lessons From The Growth Experience Till 2014) 4
1.4. 2014-2024: रूपांतरणकारी संवृद्धि का दशक (2014-2024: Decade of Transformative Growth) 4
1.5. 2014-2024 में भारत की संवृद्धि के चालक (Drivers of India's Growth in The Last Decade) 5
1.6. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां (Challenges Confronting The Indian Economy) 6
1.7. भावी राह: अमृतकाल की यात्रा (Looking Ahead: Journey of Amritkal) 7
2. भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से कारक रेजिलिएंट बनाते हैं? (What Made the Indian Economy Resilient?) 8
2.1. घरेलू अर्थव्यवस्था (Domestic Economy) 8
2.1.1. उपभोग संबंधी मांगों में लचीलापन (Resilience of Consumption Demand) 8
2.1.2. निवेश आधारित आर्थिक संवृद्धि को सक्षम करना (Enabling Investment-led Economic Growth) 9
2.1.3. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषिगत क्षेत्रक की नीतियां (Agricultural Sector Policies Ensuring Food Security) 11
2.1.4. भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाले सुधार (Reform Push to the Indian Industry) 12
2.1.5. डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी (Digital Infrastructure and Delivery of Citizen-Centric Services) 14
2.1.6. ऋण सृजन में सुधार (Credit Creation is back) 16
2.1.7. बढ़ती अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय बाजारों का विकास (Evolving Financial Markets to Support the Investment Needs of a Growing Economy) 18
2.2. समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरता बनाए रखना (Safeguarding Macroeconomic Stability) 19
2.3. मानव संसाधन: कल्याण को सक्षम बनाने के साथ विकास को संतुलित करना (Human Resources: Dovetailing Growth with Capacitating Welfare) 21
2.3.1. वेलफेयर यानी कल्याण के प्रति एक नया दृष्टिकोण (A New Approach to Welfare) 21
2.3.2. वेलफेयर के प्रति अपनाया गया नवीन दृष्टिकोण किस प्रकार लाभदायक रहा है (How has the new approach to welfare paid off) 21
2.3.3. महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास: 2047 तक लैंगिक लाभांश का दोहन (Women-led development: Tapping the Gender Dividend for India@100) 23
2.3.4. लंबी अवधि पर फोकस (Eyes on the long-term) 25
2.3.5. पिछले दशक में रोजगार की स्थिति (Employment Situation in the Past Decade) 25
2.3.6. कौशल विकास और उद्यमिता (Skill Development and Entrepreneurship) 26
2.4. भारत का बाह्य क्षेत्रक: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित मार्ग तलाशना (India's External Sector: Safely Navigating Through Uncertainties) 27
2.4.1. वस्तु व्यापार में लचीलापन (Merchandise Trade Depicted Resilience) 27
2.4.2. चालू खाते में सकारात्मक संतुलन (Comfortable Balance on Current Account) 27
2.4.3. पूंजी खाता (Capital Account) 28
2.4.4. बाह्य क्षेत्रक के लिए आगे की राह (Way Ahead for External Sector) 30
2.5. जलवायु कार्रवाई (Climate Action) 30

2.5.1. अनुकूलनशीलता को बनाए रखने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई (India's Climate Action towards Building Resilience) 30
2.6. आउटलुक (Outlook) 33

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. भारतीय अर्थव्यवस्था: अतीत, वर्तमान और भविष्य (Indian Economy: Past, Present and Future)

1.1. भूमिका (Introduction)

पिछले दशक में कई सारे निर्णायक नीतिगत कार्रवाइयों के चलते भारत के बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्रक को बढ़ावा मिला है। इसने समावेशी विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। राजकोषीय स्थिरता की एक ठोस स्थिति और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण से अर्थव्यवस्था के कमजोर पहलू भी अब मजबूती के प्रतीक बन गए हैं। कई सारे रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 और 2025 में भारत की आर्थिक संवृद्धि दर 7% या उससे अधिक रह सकती है। यह स्थिति वाकई में कोरोना महामारी के बाद एक उल्लेखनीय उपलब्धि को इंगित करती है।

1.2. भारतीय अर्थव्यवस्था और संवृद्धि का कालक्रम {The Indian Growth Story (1950 To 2014)}

- **1950 का दशक:** वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी सन् 1700 में 22.6% थी, जो घटकर वर्ष 1952 में 3.8% हो गई थी। भारत ने स्वयं को संवृद्धि और आधुनिकीकरण की राह में अग्रणी बनाने करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की।
  - इस अवधि (1952-60) के लिए **दशकीय औसत वृद्धि दर 3.9% थी।**
- **1960 का दशक:** 1962 के **भारत-चीन युद्ध,** 1965-66 के **भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965** में भयंकर सूखा, **कराधान की उच्च दरें और अर्थव्यवस्था पर व्यापक नियंत्रण** के चलते आर्थिक संवृद्धि में बाधा पैदा हुई।
  - इस दौरान भारत ने **4.1% की दशकीय औसत वृद्धि दर दर्ज की थी।**
- **1970 का दशक:** इस दशक में **रुपये का 57% अवमूल्यन, गंभीर राजनीतिक अस्थिरता, 1975 में आपातकाल लगाना** आदि प्रमुख घटनाक्रम थे। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था भी मुख्य रूप से तेल संकट के कारण आर्थिक गिरावट का सामना कर रही थी।
  - **इस दौरान भारत की दशकीय औसत वृद्धि दर में 2.9% की** गिरावट हुई थी।
- **1980 का दशक:** भारत ने **घरेलू स्तर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए** जैसे कि मूल्य नियंत्रण हटाना, आयात शुल्क में कटौती, घरेलू उद्योग को डी-लाइसेंसिंग करना आदि।
  - **बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च** और **मॉडेस्ट उदारीकरण** के चलते **सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सुधरकर 5.7% तक हो गई।**
- **1990 का दशक:** बाहरी संकट (सोवियत संघ विघटन और इराक-कुवैत युद्ध), **अनसस्टेनेबल सरकारी खर्च** और आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक माहौल के चलते **भुगतान संतुलन संकट (1990-1991) की समस्या पैदा हो गई।**
  - इसके जवाब में, भारत ने **विनियमन और व्यापार उदारीकरण से जुड़े सुधारों की शुरुआत की।**
  - इस **दशक के मध्य के बाद** बाहरी संकट **(पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट)** और **कृषि क्षेत्रक में गिरावट, सत्ता में बार-बार होने वाले बदलाव** आदि जैसे आंतरिक मुद्दों के कारण वृद्धि की गति प्रभावित हुई।
  - **1990 के दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 5.8% प्रति वर्ष थी।**
- **2000 का दशक:** 2000 के दशक की शुरुआत में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कॉर्पोरेट जगत का बेहतर प्रदर्शन, निवेश अनुकूल माहौल आदि देखा गया। 2000 के दशक में भारत की **दशकीय औसत वृद्धि दर 6.3%** प्रति वर्ष थी।
  - हालांकि, **वैश्विक वित्तीय संकट (2008)** ने संवृद्धि की गति से जुड़ी अस्थिर आधार की समस्या को उजागर कर दिया।
  - **बैंकों में बैड डेट्स बढ़ने लगा और 2018 में यह बढ़कर 11.2% के शिखर पर पहुंच गया।**

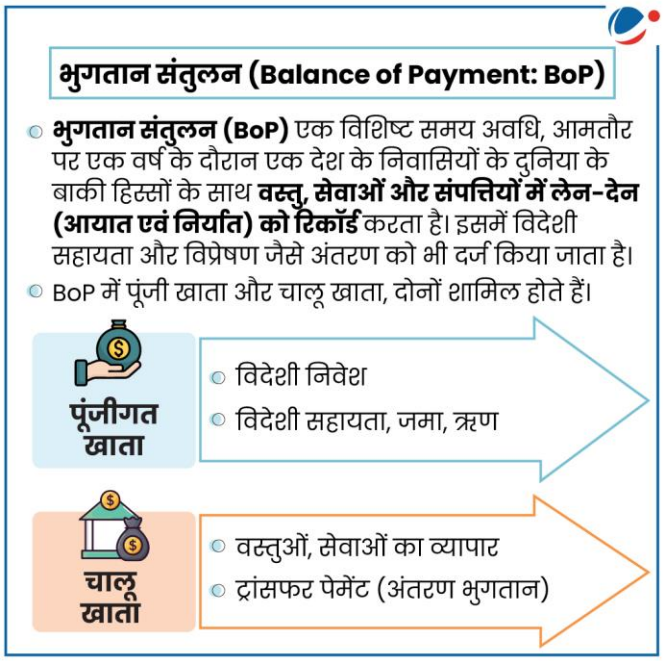

- **2009-2014:** सरकार ने **उच्च राजकोषीय घाटे** और मौद्रिक नीति में लंबे समय तक ढील देकर उच्च संवृद्धि दर को बनाए रखने का प्रयास किया। **उच्च मुद्रास्फीति के कारण नॉमिनल GDP ग्रोथ अधिक** थी।
  - भारत ने 2009-2014 के दौरान लगभग हर साल **दो अंकों वाली मुद्रास्फीति दर का सामना किया।**
  - इस दौरान देश को **"हाई ट्विन डेफिसिट"** का सामना करना पड़ा - **राजकोषीय घाटा (वित्त वर्ष 2013 में 4.9%)** और **चालू खाता घाटा (वित्त वर्ष 2013 में 4.8%)।**
  - 2009-14 के दौरान भारतीय **रुपये में सालाना 5.9%** की गिरावट आई।

1.3. 2014 तक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की यात्रा के अनुभव से लिए गए सबक (Lessons From The Growth Experience Till 2014)

- भारतीय अर्थव्यवस्था **"बंद अर्थव्यवस्था" से "खुली अर्थव्यवस्था" में परिवर्तित** हो गई।
  - भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के प्रयास में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को गति मिली।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व के स्थान पर सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व में बदल गया।**
  - 1990 और 2000 के दशक के दौरान भारत का निजी क्षेत्रक संवृद्धि और रोजगार सृजन का प्रमुख चालक बन गया।
- **प्रौद्योगिकी को संवृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में पहचान** मिली।
  - 1980 के दशक से, भारत अपनी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण लाने के लिए धीरे-धीरे और लगातार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।

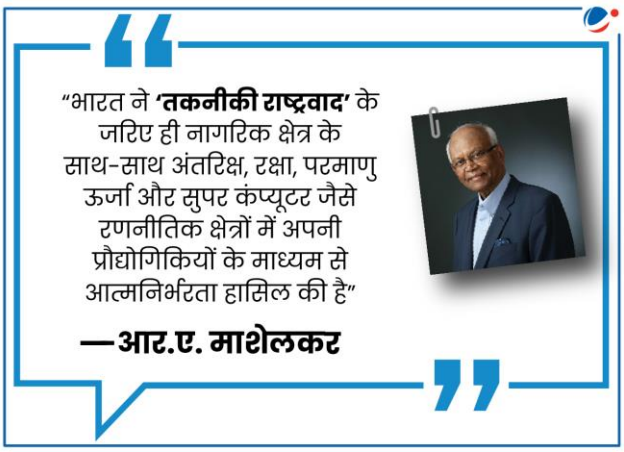

2014 में बरकरार रहीं चुनौतियां

- **संवृद्धि में गिरावट:** भारत में लगातार दो वर्षों यानी 2012-13 और 2013-14 में फैक्टर कॉस्ट पर **GDP ग्रोथ रेट 5% से भी कम** रही।
- **मुद्रास्फीति:** 2013-14 तक पांच वर्षों में खाद्य पदार्थों की WPI मुद्रास्फीति औसतन 12.2% सालाना रही थी।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** इसमें त्वरित निर्णय लेने में कठिनाइयां, सब्सिडी से जुड़ी समस्याएं, कमतर विनिर्माण क्षमता, बड़े अनौपचारिक क्षेत्रक की मौजूदगी और कम कृषि उत्पादकता आदि शामिल थीं।

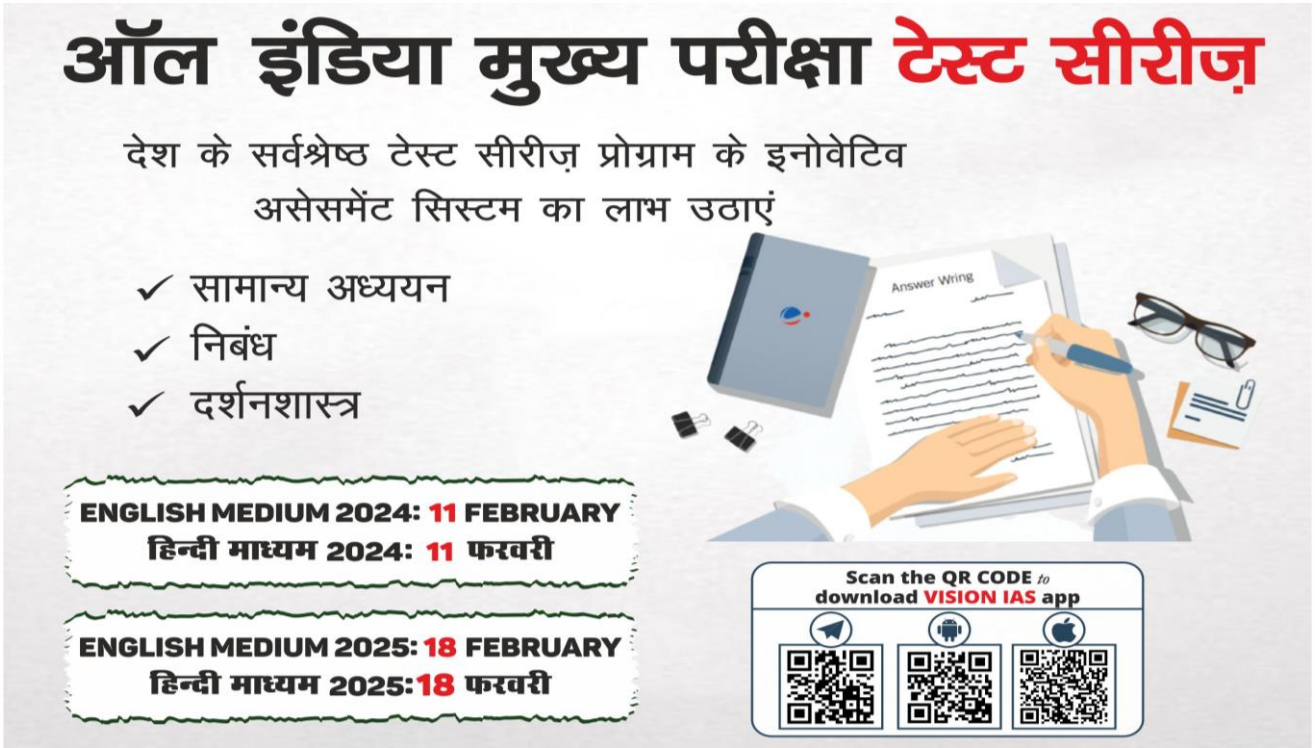

1.4. 2014-2024: रूपांतरणकारी संवृद्धि का दशक (2014-2024: Decade of Transformative Growth)

- **मजबूत और प्रभावशाली संवृद्धि:** इस दशक (2014-2024) में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर **10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।**
  - इस दशक में नीतिगत और आर्थिक सुधारों के कारण भारत **G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।**
- **इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनर्बहाली और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता प्रदर्शित की:**
  - **वैश्विक महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक संवृद्धि काफी प्रभावित हुई थी।** इस दौरान रियल GDP ग्रोथ रेट नकारात्मक (-5.83%) थी।
  - हालांकि, वैश्विक महामारी संकट के दौरान राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य संबंधी व्यापक प्रयासों के जरिए और **सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने भारत की आर्थिक पुनर्बहाली को संभव बनाया।**
  - **2023-24 में, वर्तमान अनुमान के अनुसार, भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि यह वित्त वर्ष 2021-22 में 9.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत थी। शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% रह गई है।**
    - रेजिलिएंट सेवा निर्यात और तेल आयात के घटते बिल के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का **चालू खाता घाटा GDP के 1%** पर पहुंच गया है।
  - आजादी के बाद पहले 67 वर्षों में भारत में **74 हवाई अड्डे** बनाए गए। **पिछले 9 वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो गई है।**
  - विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 में 723 थी, जो बढ़कर 2023 में 1,113 हो गई। साथ ही, **उच्चतर शिक्षा में कुल छात्र नामांकन** 2014 में 3.4 करोड़ था, जो बढ़कर 2023 में 4.1 करोड़ तक पहुंच गया।
    - इस संबंध में छात्राओं का **सकल नामांकन अनुपात (GER)[1] 2020 में 27.9 हो गया,** जबकि वित्त वर्ष 2009-10 में यह 12.7 प्रतिशत था।

1.5. 2014-2024 में भारत की संवृद्धि के चालक (Drivers of India's Growth in The Last Decade)

- **ट्विन बैलेंस शीट समस्या का समाधान करने हेतु सुधार:** इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) का पुनर्पूंजीकरण और विलय करना; सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 में संशोधन करना; इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 पारित करना आदि जैसे कदम उठाए गए।
  - IBC ने व्यवसायों को सम्मानजनक एग्जिट (परिसमापन) प्रदान करके कारोबारी माहौल में सुधार किया है। **सितंबर 2023 तक, IBC के चलते 2,808 कॉर्पोरेट ऋणदाताओं ने इसका लाभ उठाया था।**

शब्दावली को जानें

- **ट्विन बैलेंस शीट समस्या:** ट्विन बैलेंस शीट एक ऐसी स्थिति है जहां बैंक गंभीर तनाव में होते हैं और कॉर्पोरेट्स अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं।

- **विनियामकीय व्यवस्था का सरलीकरण:** रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 ने लेन-देन की पारदर्शी संस्कृति स्थापित की है, जिससे काले धन का प्रचलन कम हो गया है।
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत **1 लाख से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएं और 72,012 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत** हैं।
- **जीवन जीने और व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Living & Ease of Doing Business):** यह एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST), कॉर्पोरेट और आयकर दरों को कम करने, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड को करों से छूट देने और लाभांश वितरण कर[2] को हटाने से संभव हुआ है।
  - **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **छोटे आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर** किया गया है। साथ ही, डिफ़ॉल्ट के 1,400 से अधिक मामलों का निर्णय न्यायालय में जाए बिना ही किया गया है।
  - लगभग 25,000 विनियामकीय नियमों के अनावश्यक पालन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, 1,400 से अधिक पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया गया है।

[1] Gross Enrolment Ratio

[2] Dividend Distribution tax

- **निजी क्षेत्रक के साथ सरकार की भागीदारी:** आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के क्रम में **नई "सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSE) नीति"** भी जारी की गई है। इसके जरिए PSEs में सरकार की भागीदारी को कम किया गया है।
  - भारत की विनिर्माण क्षमताओं और सभी उद्योगों में निर्यात को बढ़ाने के लिए **मेक इन इंडिया** कार्यक्रम शुरू किया गया।
  - घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं विनिर्माण उद्योग में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए कंपनियों को **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)**[3] प्रदान किए जा रहे हैं।
  - निजी क्षेत्रक हेतु व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को खोल दिया गया है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)[4] क्षेत्रक:** MSMEs के संबंध में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, MSMEs की परिभाषा में बदलाव, MSMEs के लिए भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए TReDS (TReDS)[5] प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जैसे कदम उठाए गए हैं।
  - मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2016 में 452 थी, जो बढ़कर 2023 में 98,000 से भी अधिक हो गई है।

GST के प्रभाव

- GST के चलते **कर आधार (Tax Base) बढ़ा** है, अनुपालन प्रक्रिया के बोझ में कमी आई है, राज्यों के मध्य वस्तुओं का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ा है।
- **GST प्रणाली से पहले की तुलना में कर संग्रह में लगातार उछाल हुआ है।** वित्त वर्ष 2018 में औसत मासिक सकल संग्रह 0.9 लाख करोड़ रुपये था जो लगातार बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2023 में 1.5 लाख करोड़ हो गया।
- **GST करदाताओं की संख्या GST की शुरुआत के समय 66 लाख थी, जो बढ़कर 2022 में 1.4 करोड़ हो गई है।**

- **लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर:** रोड कनेक्टिविटी (**भारतमाला**), पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (**सागरमाला**), विद्युतीकरण, रेलवे का अपग्रेडेशन, नए हवाई अड्डे/ हवाई मार्ग (उड़ान/ UDAN), और **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022** आदि के लिए समर्पित प्रोग्राम्स ने अवसंरचना के आधुनिकीकरण को संभव बनाया है।
  - केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय मार्च 2014 में **GDP के 2.8% के बराबर था, जो बढ़कर 2023-24 (बजट अनुमान) में 4.5%** हो गया है।
- **डिजिटलीकरण संबंधी सुधार:** डिजिटल अवसंरचना के चलते डिजिटल आइडेंटिटी बनाने, वित्त तक बेहतर पहुंच, बाजारों तक पहुंच, लेन-देन की लागत कम करने और कर संग्रह में सुधार संभव हुआ है।
- **समावेशी कल्याणकारी नीतियां: 10.11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन** दिए गए हैं। गरीबों के लिए **11.72 करोड़ शौचालय और 2.6 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं।**
  - **आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 6.27 करोड़ मरीज अस्पताल में भर्ती** हुए।

1.6. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां (Challenges Confronting The Indian Economy)

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर **बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन** और हाइपर-ग्लोबलाइजेशन में गिरावट का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो रही है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से नौकरी की सुरक्षा को खतरा है।** IMF का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत रोजगार को AI से खतरा है।
- उद्योग के लिए **प्रतिभाशाली और आवश्यक कुशल कार्यबल की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।

चुनौतियों का समाधान करने में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना है। लगभग 1.3 करोड़ लोगों ने PMKVY (दिसंबर, 2023) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **भारत नवीकरणीय ऊर्जा (RE) को बढ़ावा दे रहा है और कोयले के उपयोग को कम कर रहा है।** बड़ी जलविद्युत परियोजना सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 179.57 गीगावॉट (नवंबर, 2023) है।

[3] Production Linked incentives

[4] Micro, Small, and Medium Enterprises

[5] ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम/ Trade Receivable Discounting System

- **समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - **भारत में इंटरनेट की पहुंच:** इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, **2022 में भारत में इंटरनेट की पहुंच 50% का आंकड़ा पार कर गई।** यह 2014 के बाद से लगभग तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी को दर्शाता है।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** आधार और DBT के चलते अलग-अलग योजनाओं से 1,167 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड ट्रांसफर किया जा चुका है।
  - **वित्तीय समावेशन: पी.एम. जन धन योजना** के तहत कुल लाभार्थी जनवरी, 2024 तक 51.5 करोड़ थे, जो मार्च 2015 के बाद से 3.5 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
    - **जनधन खाताधारकों में लगभग 56% महिलाएं** हैं, और **इनमें से 2/3 (लगभग 66%) खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।**
    - **कोविड टीकाकरण: CoWin ऐप के तहत** 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी को **221 करोड़ टीकाकरण खुराक लगाई गई हैं।**
    - **अंतरिक्ष क्षेत्रक:** जुलाई, 2023 तक भारत ने **431 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए थे,** जिनमें से 396 जून, 2014 के बाद लॉन्च किए गए हैं।

1.7. भावी राह: अमृतकाल की यात्रा (Looking Ahead: Journey of Amritkal)

पिछले दस वर्षों (2014-24) में किए गए सुधारों ने एक **सक्षम व साझेदारी-आधारित गवर्नेंस** की नींव स्थापित की है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए, भारत मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी "अमृत काल" यात्रा शुरू कर रहा है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से कारक रेजिलिएंट बनाते हैं? (What Made the Indian Economy Resilient?)

2.1. घरेलू अर्थव्यवस्था (Domestic Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदर्शित रेजिलिएंस या लचीलापन

- विश्व के बहुत कम देशों ने भारत की तरह **कोविड-19 महामारी के बाद लगातार हर मोर्चे पर रिकवरी** को बनाए रखा है।
- कोविड महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में **भारतीय GDP की ग्रोथ रेट नकारात्मक थी।** इसके बाद के **दो वित्त वर्षों** (2021-22 और 2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था की **ग्रोथ रेट 7% से ऊपर** ही रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष-2023-24 में भारत की **रियल GDP ग्रोथ रेट 7.3% रहने** का है।
  - मात्रा (Volume) के आधार पर कुल **सकल मूल्यवर्धन** (GVA)[6] में **विनिर्माण क्षेत्रक** की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 17.2% थी, जो **वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 17.7%** हो गई।
  - इसी तरह, मात्रा के आधार पर में कुल GVA में **सेवा-क्षेत्रक की हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2013-14 में 51.1% थी, जो **वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 54.6%** हो गई।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था में** रेजिलिएंस को **बेरोजगारी की दर में गिरावट, रेल द्वारा माल के परिवहन और पोर्ट-कार्गो परिवहन में वृद्धि और ई वे बिल जारी करने की संख्या में लगातार वृद्धि** आदि के रूप में भी देखा जा सकता है।

2.1.1. उपभोग संबंधी मांगों में लचीलापन (Resilience of Consumption Demand)

प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE)[7] में वृद्धि

- कोविड-19 महामारी के बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर **संवृद्धि के एक मुख्य चालक** के रूप में उभरा है। भू-राजनीतिक संघर्ष, घटती वैश्विक मांग जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद PFCE भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- चालू कीमतों पर GDP में **PFCE** की हिस्सेदारी कोविड महामारी की शुरुआत से पहले के 8 वर्षों में औसतन 58.4% थी। यह वित्त वर्ष 2023-24, 2022-23 और 20221-222 में बढ़कर औसतन 60.8% हो गई।

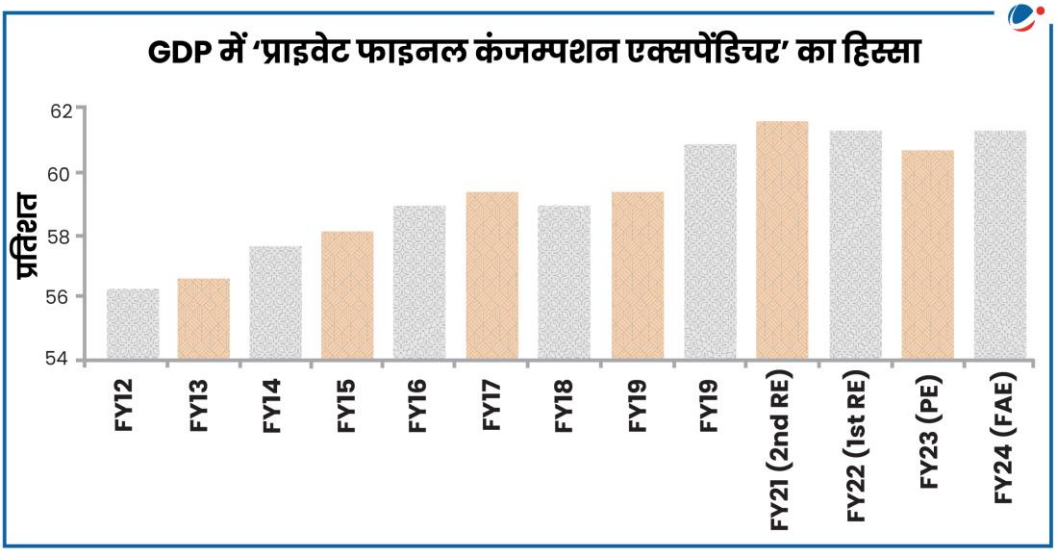

  - प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि **टिकाऊ (ड्यूरेबल) व अर्द्ध-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं सहित** सभी घटकों में लगभग संतुलित रही है।
  - सोशल डिस्टेंसिंग पर प्रतिबंधों में ढील से **सेवा क्षेत्रकों की मांग में फिर से वृद्धि** देखी जा रही है।

[6] Gross Value Added

[7] Private Final Consumption Expenditure

अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में योगदान देने वाले कारक

- **मजबूत उपभोग आधार:** यह कोविड-19 के आने से पहले के 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय में मजबूत वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है।
- **कोविड-19 संकट का बेहतर प्रबंधन:** बेहतर प्रबंधन के चलते एक सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ और लोगों को भविष्य में अधिक आय का विश्वास मिला। इससे लोगों द्वारा खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।

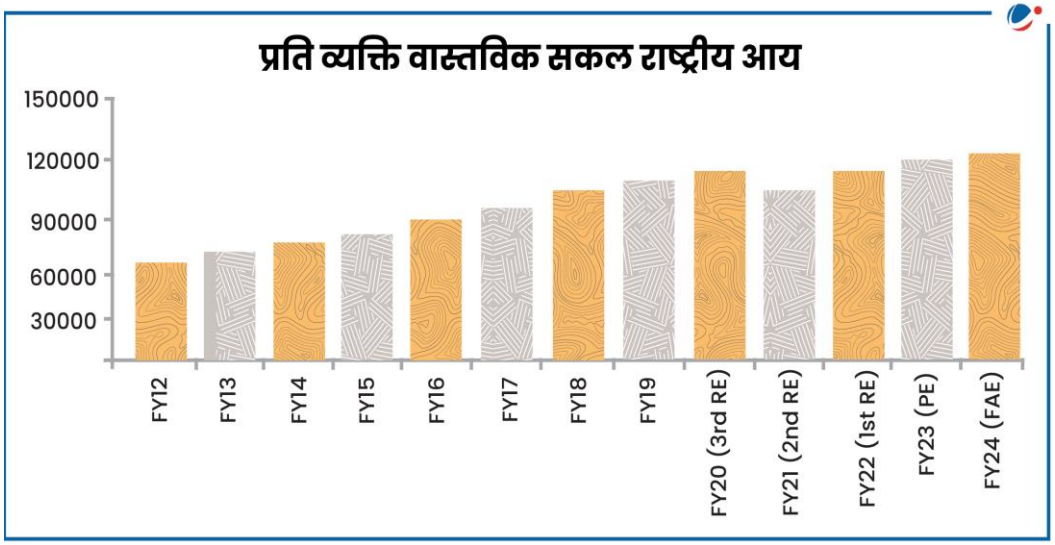

- **निवेशकों में विश्वास:** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाया, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के दौरान शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि हुई।
  - भारत में डीमैट खातों की संख्या दिसंबर 2023 तक बढ़कर 13.9 करोड़ हो गई, जो **मार्च 2014 की तुलना में 536% की वृद्धि है।**
- **सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना[8] के विकास पर जोर:** डिजिटलीकरण ने कोविड से पहले और बाद के चरण के दौरान, निजी उपभोग को बढ़ाने में प्रत्यक्ष तौर पर मदद की है।
  - कोविड (वैश्विक महामारी) ने टेली-मेडिसिन देखभाल, डिजिटल भुगतान और किराने के सामान की ऑनलाइन खरीदारी को तेजी प्रदान की। साथ ही, UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने ई-कॉमर्स के विकास में काफी सहायता प्रदान की है।
- **ग्रामीण भारत का सामाजिक और आर्थिक समावेशन:** सरकार के कल्याणकारी प्रयासों ने सभी को शामिल करते हुए शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम किया है। इसके चलते ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है और ब्रांडेड उत्पादों पर खर्च करने की आदत बढ़ी है। साथ ही, इससे मध्यम वर्ग का विस्तार भी हुआ है।
  - **पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE)** की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू आय में काफी बदलाव हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके चलते मध्यम वर्ग की संख्या 2021 के 432 मिलियन से बढ़कर 2031 में 715 मिलियन हो जाएगी।
- **अन्य कारक:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अनुपालन संबंधी नियमों में कमी,
  - कानून को सरल बनाना,
  - विभिन्न क्षेत्रकों को खोलना,
  - सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश, और
  - व्यावहारिक मौद्रिक नीति आदि।

2.1.2. निवेश आधारित आर्थिक संवृद्धि को सक्षम करना (Enabling Investment-led Economic Growth)

परिचय

समग्र रूप से देखें तो **पिछले लगातार तीन वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अर्थव्यवस्था में निवेश दर वित्त वर्ष 2015-16 के स्तर को पार कर गई है।** अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रकों यानी सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और हाउसहोल्ड निवेश में वृद्धि के चालक रहे हैं।

[8] Public Digital Infrastructure

21वीं सदी के पहले दो दशक

- **पहला दशक:** इस दशक में अत्यधिक ऋण लेने और अति-आशावाद के कारण **व्यापक निवेश दर** देखने को मिली, जो अंततः अव्यवहारिक साबित हुई।
- **दूसरा दशक:** इस दशक के दौरान GDP के सापेक्ष निवेश की दर में कमी आई। बैंक कॉर्पोरेट्स को ऋण देने में अनिच्छुक थे। इसके कारण कॉर्पोरेट्स को संपत्ति बेचकर और ऋण चुका कर अपनी बैलेंस शीट ठीक करना पड़ा।
  - इस दौरान उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च चालू खाता घाटा और निरंतर दोहरे अंक वाली मुद्रास्फीति के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मैक्रो-इकॉनॉमिक अस्थिरता भी मौजूद थी।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था को "**फ्रेजाइल फाइव" उभरती अर्थव्यवस्थाओं** के क्लब में शामिल किया गया था।

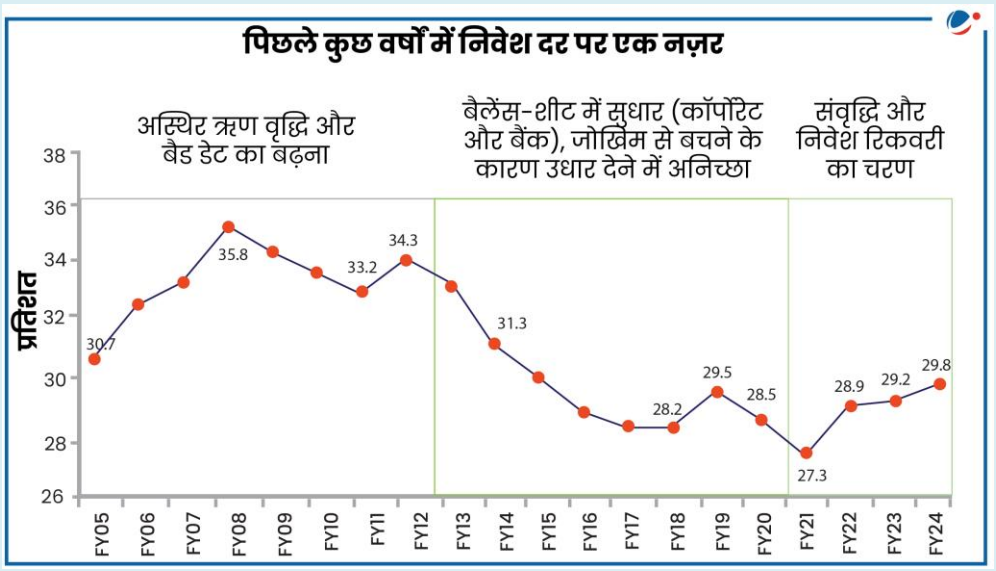

हाल के वर्षों में 'निवेश' आर्थिक संवृद्धि के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरा है।

- **निवेश में बढ़ोतरी पर आधारित सुधार और बेहतर बैलेंस शीट:** इनके कारण निजी कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि हो रही है और बैंक अधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक का पूंजीगत व्यय**: यह वित्त वर्ष 2014-15 में 5.6 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस अवधि के दौरान, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 5.1 गुना की वृद्धि हुई; पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान में 2.8 गुना की वृद्धि हुई; और सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के संसाधनों में 2.1 गुना की वृद्धि हुई।
  - सरकार ने अपने राजकोषीय व्यय को पुनर्संतुलित किया। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय हिस्सा 12% था, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 22% कर दिया गया है।

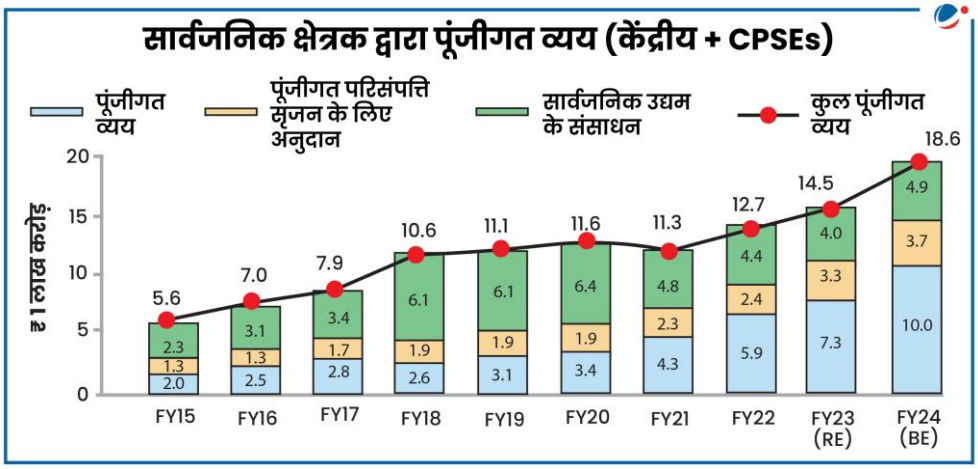

- **अवसंरचना से संबंधित आपूर्ति-पक्ष की कमियों के समाधान पर जोर**: सरकार ने निर्माण में देरी, अपर्याप्त वित्त-पोषण और कानूनी तथा भूमि संबंधी मुद्दों आदि के कारण रुकी हुई अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा किया है।
  - **प्रगति/ परियोजना निगरानी समूह (PMG)[9] पोर्टल**: इस' पोर्टल पर जून 2014 से 49.4 लाख करोड़ रुपये की 2,169 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 12.2 लाख करोड़ रुपये की 676 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- **महामारी के बाद के वर्षों में निजी पूंजीगत व्यय में पुनः वृद्धि के संकेतक**: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)[10] के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत वस्तु सूचकांक और अवसंरचना/ निर्माण वस्तु सूचकांक[11] में क्रमशः 7.5% और 11.1% की वृद्धि हुई है।

[9] Project Monitoring Group

[10] Index of Industrial Production

[11] Infrastructure/Construction goods index

- **हाउसहोल्ड क्षेत्रक में निवेश**: रियल एस्टेट की कीमतों में बढ़ोतरी और उच्च ब्याज दरों के बावजूद, आवासों की बिक्री और आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत में तेजी देखी गई है। यह आय की पुनर्बहाली और भविष्य में आय को लेकर सकारात्मकता को प्रमाणित करता है।
    - कुल **सकल स्थिर पूंजीगत निर्माण** (GFCF)[12] में हाउसहोल्ड क्षेत्रक के निवेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

2.1.3. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषिगत क्षेत्रक की नीतियां (Agricultural Sector Policies Ensuring Food Security)

परिचय

वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिस्थितियों में अस्थिरता के बावजूद, इस क्षेत्रक ने उल्लेखनीय लचीलेपन या क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह क्षेत्रक वित्त वर्ष 2004-05 से वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक उच्च औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इस क्षेत्रक ने वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 4.0% की दर की वृद्धि दर्ज की है।

कृषि क्षेत्रक की स्थिति

- भारत के **GVA (सकल मूल्य वर्धन) में कृषि क्षेत्रक का हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में 18%** रहने का अनुमान है।
- **वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मीट्रिक टन** था, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 14.1 मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है।
    - भारत दुनिया भर में **दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक** है। साथ ही, भारत फलों, **सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** भी है।
- **भारत का कृषिगत निर्यात** वित्त वर्ष 2021-22 के रिकॉर्ड को पार करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में **4.2 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच गया।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **किसानों को लाभकारी मूल्य:** 2018-19 से, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल फसलों के लिए **अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50% लाभ निर्धारित किया।**
    - 2023-24 में मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई और इसके बाद रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है।
    - **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान** (पी.एम.-आशा) योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी।
        - इस मूल्य समर्थन योजना का उद्देश्य **भारत की दालों, खाद्य तेल और वाणिज्यिक फसलों पर आयात निर्भरता को कम करना** और इन फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
- **किसानों को वित्तीय सहायता:** प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), 2019 के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके तहत दिसंबर, 2023 तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं।
    - **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (2016)** न रोकी जा सकने वाली प्राकृतिक आपदाओं के मामले में **किफायती मूल्य पर फसल बीमा** प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 2016-17 से लगभग 55 करोड़ किसान आवेदनों का फसल बीमा किया गया है और बीमा दावों के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
    - **प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना** के तहत 23.4 लाख लघु और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान किया जाता है।
- **डिजिटल समावेशन:** e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) मंडियों के डिजिटल रूप से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य तलाशने वाला एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म है। साथ ही, यह ऑनलाइन भुगतान सुविधा को भी बढ़ावा देता है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर 8 करोड़ किसान और 2.5 लाख व्यापारी पंजीकृत हैं।

[12] Gross Fixed Capital Formation

- **e-NAM के साथ एकीकृत कृषि उपज बाजार समितियों[13] की संख्या** 2016 में 250 थी, जो बढ़कर **2023 में 1,389 हो गई है।** e-NAM प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले कुल व्यापार का मूल्य 2017 में 0.3 लाख करोड़ था, जो बढ़कर नवम्बर 2023 में 3 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

- **खाद्य सुरक्षा:** कोविड-19 आपदा के दौरान शुरू की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी, 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था।
- **अन्य पहलें:** इसमें फसल कटाई के बाद की अवसंरचना में निवेश के लिए **कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund)**; पीएम किसान संपदा योजना; पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल घटक जैसी संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना; प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर

- **एग्रीस्टैक:** यह कृषि संबंधी योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक अखिल भारतीय डिजिटल रजिस्ट्री के रूप कार्य करता है।
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs)[14] का कम्प्यूटरीकरण:** इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है।
  - एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क (National Software Network) के माध्यम से नाबार्ड के साथ 62,318 PACSs को जोड़ा गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रणालियों में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **ड्रोन का उपयोग:** सरकार किसानों के खेतों में ड्रोन के उपयोग के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

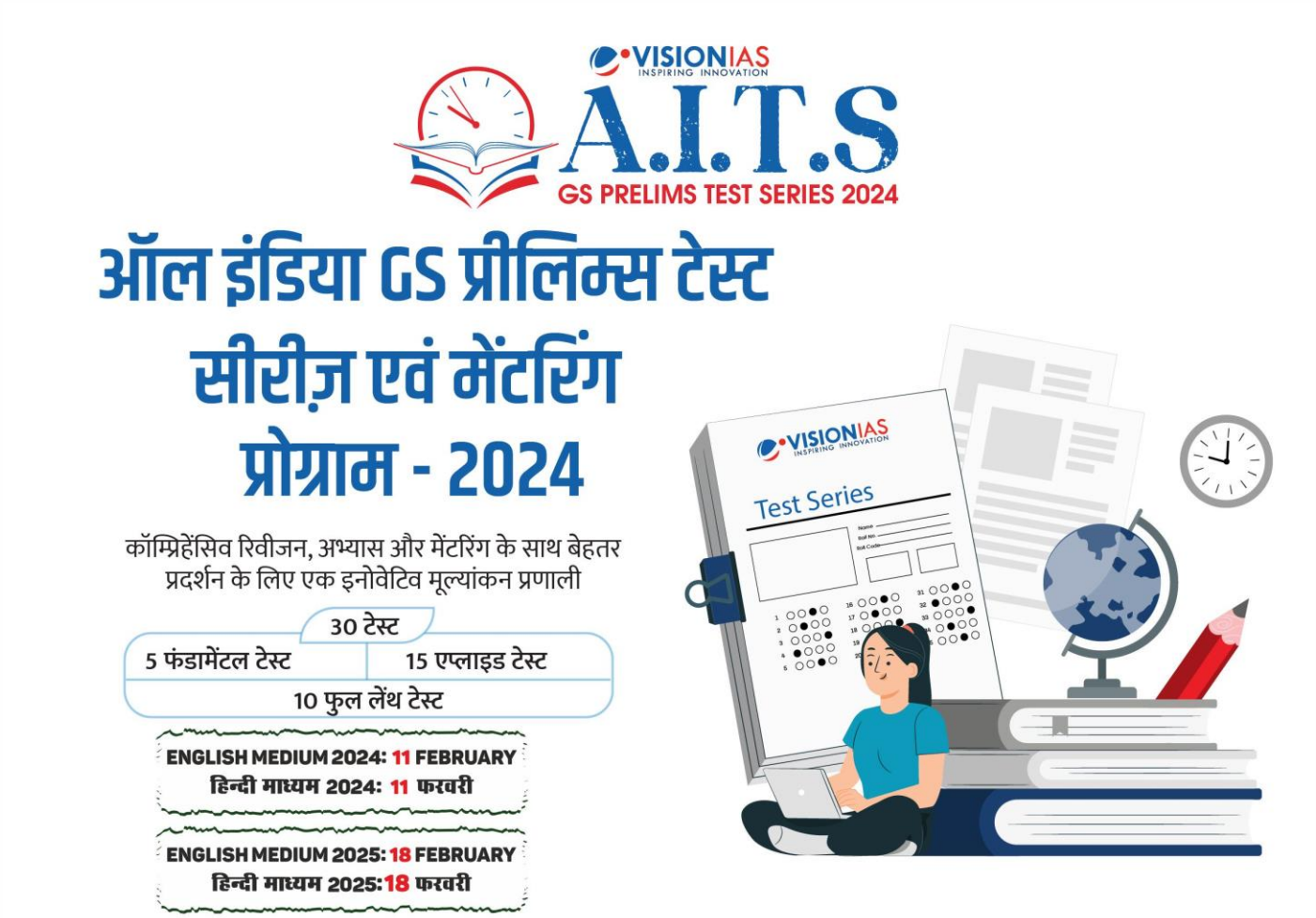

[13] Agricultural Produce Market Committees APMCs

[14] Primary Agricultural Credit Societies

2.1.4. भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाले सुधार (Reform Push to the Indian Industry)

परिचय

वित्त वर्ष **2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक औद्योगिक ग्रोथ रेट बढ़कर 7.1% प्रति वर्ष** हो गई। यह ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2013-14 तक 5.5% थी। कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक क्षेत्रक काफी प्रभावित हुआ। हालांकि, हाल के वर्षों में **बहुआयामी सुधारों** के कारण, वित्त वर्ष **2021-2024** के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में प्रति वर्ष 8% की मजबूत ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है।

प्रमुख पहलें

- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[15] योजना**: मेक इन इंडिया के तहत **PLI** योजना निर्धारित क्षेत्रकों के विनिर्माताओं को उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई है।
  - इस योजना के तहत **1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ** है। इससे 8.7 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन/ बिक्री हुई तथा 7 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं।
  - इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान के चलते **निर्यात 3.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।**
- **स्टार्टअप इंडिया:** इसके तहत अक्टूबर 2023 तक मान्यता प्राप्त 1.14 लाख स्टार्टअप ने 12 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं।
  - **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** (ONDC) के तहत नवंबर 2023 में 6.3 मिलियन से अधिक लेन-देन हुआ।
- **विनियामकीय सुधार**: इसके तहत सरकार ने 3,600 अनुपालन को अपराध मुक्त करके और जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2023 पारित करके ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार किया है।
- **लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सुधार**: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत 'यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म' (ULIP) को 8 विभिन्न मंत्रालयों की 35 प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर 699 औद्योगिक इकाइयां भी पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए **लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं की दक्षता को सरल बनाना और सुधारना है।**
  - दिसंबर 2023 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार **वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष लॉजिस्टिक लागत में 0.8 से 0.9% की गिरावट आई है।**
  - प्रमुख पत्तनों पर औसत टर्नअराउंड टाइम (प्रति दिन) वित्त वर्ष 2003-04 से वित्त वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान 4.2 दिन था, जो घटकर वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.9 दिन रह गया है।

MSMEs के लिए किए गए सुधार

- केंद्रीय बजट (वित्त वर्ष 2023-24) के तहत MSMEs के लिए समय पर भुगतान को सुगम बनाया गया। इसके तहत किए गए भुगतान पर व्यय के सापेक्ष कर में कटौती तभी मिलेगी, जब भुगतान वास्तव में किया गया हो।
- **MSMEs विकास अधिनियम, 2006**: इसकी धारा 15 से 24 के अनुसार, खरीदार द्वारा MSMEs को भुगतान में देरी की स्थिति में खरीदार को भुगतान की राशि पर ब्याज देना होगा।
  - इस तरह के ब्याज का भुगतान दंडात्मक प्रकृति का होता है। इसलिए ऐसे ब्याज के भुगतान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत कोई कटौती नहीं मिलती है।
- **उद्यम पोर्टल और उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म (Udyam Assist Platform: UAP)**: दोनों ने MSMEs संबंधी इंफॉर्मेशंस को एकीकृत करने में सहायता की है।
  - उद्यम पोर्टल पर 2.24 करोड़ MSMEs पंजीकृत हैं और UAP पर लगभग 1.2 करोड़ इकाइयां पंजीकृत हैं।
- **पी एम विश्वकर्मा (2023)**: इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को शुरुआत से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करना है।
  - दिसंबर, 2023 तक इसके तहत 48.8 लाख नामांकन हो चुके हैं।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** इसके तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 25.98 लाख करोड़ रुपये की राशि का ऋण प्रदान किया जा चुका है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट**: इस कोष की राशि को बढ़ाया गया है। इसके तहत 2023 में ऋण की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई।
- **इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना**: यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई है। इसके तहत 2.4 लाख करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी प्रदान की गई है।

[15] Production Linked Incentive

- **MSMEs के लिए ऋण:** पिछले दो वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा MSMEs को प्रदान किये गए ऋण में 16.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा MSMEs को प्रदान किए गए ऋण का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात सितंबर 2022 में 7.7% था, जो घटकर सितंबर 2023 में 4.7% हो गया।

2.1.5. डिजिटल अवसंरचना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी (Digital Infrastructure and Delivery of Citizen-Centric Services)

परिचय

कोविड-19 महामारी के बाद की आर्थिक रिकवरी ने भारत की नवीन क्षमताओं को प्रकट किया है। उदाहरण के लिए मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)।

भारत में ई-कॉमर्स बाजार

- भारत का ई-कॉमर्स तेजी से आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए- वित्त वर्ष 2022 की तुलना में **वार्षिक सकल व्यापारिक मूल्य (GMV)[16] में 23.5% की वृद्धि** हुई है।
- 'इंडिया ई-कॉमर्स इंडेक्स 2023' पर यूनीकॉमर्स (UNICOMMERCE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में **कुल ऑर्डर वॉल्यूम (किए गए ऑर्डर की मात्रा) में 26.2% की वृद्धि** देखी गई थी।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रसार, तीव्र शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग आदि ऐसे कारक हैं, जिन्होंने भारत के ई-कॉमर्स बाजार की संवृद्धि को प्रेरित किया है।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया स्टैक)

- **इंडिया स्टैक में परस्पर जुड़ी हुई तीन लेयर्स मौजूद हैं-**
  - **पहचान लेयर (Identity Layer):** आधार से पहले 25 नागरिकों में से केवल 1 के पास किसी प्रकार का औपचारिक पहचान प्रमाण था। इसके अलावा, 4 नागरिकों में से केवल 1 के पास बैंक खाता था।
  - **भुगतान लेयर (Payments Layer):** एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)[17], आधार पेमेंट्स ब्रिज और आधार सक्षम भुगतान सेवा के कारण कैशलेस भुगतान में भारी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में देखने को मिली है।
    - **UPI ट्रांजैक्शन** का मूल्य वित्त वर्ष 2017 के **₹0.07 लाख करोड़ से बढ़कर** वित्त वर्ष 2024 में **₹143.4 लाख करोड़** हो गया है।
    - ACI वर्ल्डवाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत 2022 में वैश्विक रियल-टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में अग्रणी** था।
  - **डेटा लेयर (Data Layer):** इसने **ई-के.वाई.सी. लागत को ₹1000 से घटाकर मात्र ₹5** कर दिया है। अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से लगभग **4.5 मिलियन व्यक्तियों और कंपनियों को लाभ** हुआ है (IMF की "स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स" रिपोर्ट, 2023)।

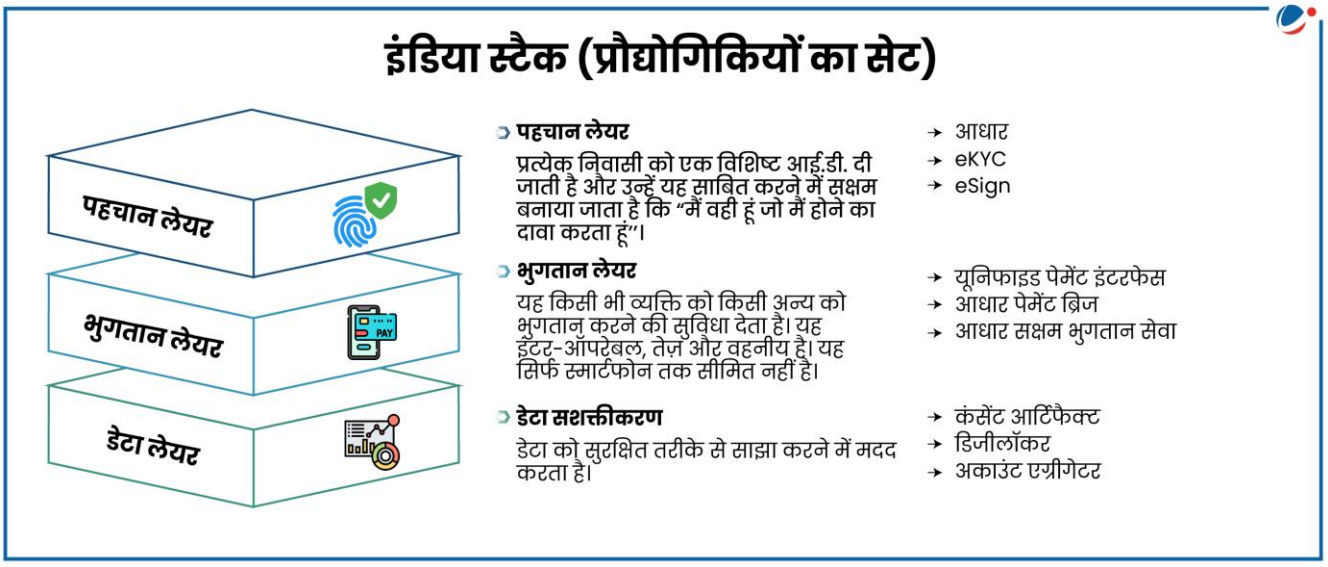

[16] Gross Merchandise Value

[17] Unified Payments Interface

- इंडिया स्टैक ने 2017 में **GST[18] के प्रवर्तन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 2023 में, GSTN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) ने लगभग 140 लाख सक्रिय करदाताओं को सेवा प्रदान की थी। यह संख्या अप्रैल 2018 में 105 लाख थी।
- **भारत के मजबूत DPI ने नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी अभिशासन सेवाएं प्रदान** करते हुए देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्षम बनाया है।

इंडिया स्टैक की संवृद्धि को सक्षम बनाने वाले कारक

- **विमुद्रीकरण (Demonetisation)** के कारण भुगतान के गैर-नकद रूपों के उपयोग में वृद्धि हुई है।
- **टेलीकॉम क्षेत्रक** में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और भेदभावपूर्ण डेटा शुल्क पर प्रतिबंध ने दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है।
- **मार्च 2014 में प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक की औसत मासिक डेटा खपत 61.7MB** थी। यह खपत जून 2023 में **18.4GB** तक बढ़ गई थी।
- **भारत में प्रति GB औसत डेटा टैरिफ दुनिया में तीसरा सबसे कम है।** 2014 में भारत में मोबाइल डेटा टैरिफ ₹269/ GB था, जो 2023 में घटकर ₹10.1/ GB हो गया है।

अन्य प्रमुख पहलें

- **प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY):** PMJDY खाते 14.7 करोड़ (मार्च 2015) से बढ़कर 51.5 करोड़ (जनवरी 2024) हो गए हैं। इससे भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** डुप्लीकेट/ फर्जी लाभार्थियों को हटाते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत लीकेज को रोका गया है। इस प्रकार, मार्च 2022 तक सरकार ने **₹2.7 लाख करोड़** बचाए हैं।
  - दिसंबर 2023 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में ₹33.6 लाख करोड़ से अधिक का अंतरण किया गया है।
- **आरोग्य सेतु और कोविन ऐप्स:** इससे वायरस को रोकने में मदद मिली है और टीकाकरण सुविधाजनक हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था को जल्दी फिर से गति देने में मदद मिली है।
- **पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA):** इसे डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ महामारी के दौरान लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था।

देश की मजबूत डिजिटल व्यवस्था का प्रभाव

- **इसने वित्तीय समावेशन में सुधार** किया है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है। साथ ही, इसने कर आधार को भी बढ़ाया है।
  - द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार, भारत ने अपने वित्तीय समावेशन के लिए जो पिछले आठ से दस वर्षों में हासिल किया है, उसे हासिल करने में अन्य देशों को औसतन 47 साल लग गए हैं।
  - महामारी के शुरुआती महीनों में, लगभग **87% गरीब परिवारों को डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग से कम-से-कम एक लाभ** प्राप्त हुआ था।
- भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद तीसरी सबसे बड़ी बढ़ती फिनटेक अर्थव्यवस्था बन गया है।**
- **सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है।** साथ ही, वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

[18] Goods and Services Tax

- महामारी के प्रकोप के बाद **डिजिटलीकरण की बढ़ती मांग; सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को प्राथमिकता तथा वैश्विक क्षमता केंद्रों** (GCC)[19] के औचक प्रसार की वजह से व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिला है।
  - **अत्यधिक कुशल कार्यबल** की उपलब्धता के कारण भारत में GCC की स्थापना हुई है। GCC का **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1% से अधिक का योगदान है,** जो भारत के सेवा निर्यात को लचीलापन प्रदान करता है।

2.1.6. ऋण सृजन में सुधार (Credit Creation is back)

बैंकिंग क्षेत्रक की स्थिति

- **बैंक ऋण:** हालिया वर्षों में, कोविड-19 महामारी के बाद निरंतर मांग और मजबूत आर्थिक सुधारों के कारण इसमें **अभूतपूर्व वृद्धि** देखी गई है।
  - **वित्त वर्ष 2023 के दौरान गैर-खाद्य बैंक ऋण में 15% की दर से वृद्धि** हुई थी। यह बढ़ोतरी पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक थी।
  - नवंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार **MSMEs को दिए गए बैंक ऋण** ने वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक **14.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर** (CAGR)[20] दर्ज की है।
  - वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 के बीच **बुनियादी ढांचा क्षेत्रक को दिए गए बैंक ऋण** ने 4.2% की CAGR दर्ज की है।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक:** ऋण प्रदायगी की फिर से शुरुआत होने से **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) के लाभ मार्जिन में सुधार** हुआ है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने **पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation)** सहित अन्य विविध उपाय किए हैं।
  - **PSBs के विलय** से बैंकिंग क्षेत्रक का वित्तीय लचीलापन और बढ़ सकता है।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs):** इन कंपनियों का ऋण बाजार बैंकों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा उनके **पूंजी स्तर, परिसंपत्ति गुणवत्ता और तरलता में उल्लेखनीय सुधार** के कारण हुआ है।
  - NBFCs को मजबूत करने के लिए **लागू किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - NBFCs के बढ़ते आकार, जटिलता और परस्पर संबद्धता को ध्यान में रखते हुए स्केल-आधारित एक अपडेटेड विनियामक फ्रेमवर्क का प्रवर्तन किया गया है। साथ ही, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क को NBFCs के लिए भी लागू किया गया है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

- सरकार और RBI के सुधारों के परिणामस्वरूप कॉरपोरेट्स व बैंकों की **"ट्विन बैलेंस शीट समस्या" "ट्विन बैलेंस शीट लाभ" में बदल** गई है।

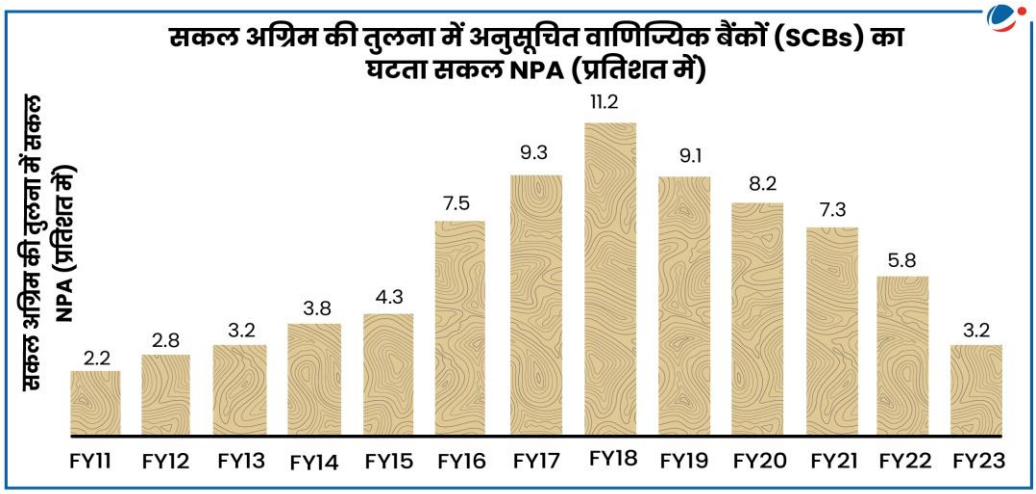

  - सितंबर 2023 में **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPAs) और निवल NPAs** में कई वर्षों के निचले स्तर पर गिरावट आई थी।

[19] Global Capability Centres

[20] Compound Annual Growth Rate

- **RBI द्वारा सुधार:** RBI ने वित्तीय क्षेत्रक में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2015 में **'एसेट क्वालिटी रिव्यू' (AQR) और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क** को लागू किया था।
- **सरकार द्वारा सुधार:** सरकार 2016 में **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के साथ IBC** लेकर आई थी। इससे **बैड लोन्स (अशोध्य ऋण) के त्वरित समाधान** में मदद मिली है।
  - IBC ने 808 कॉरपोरेट कर्जदारों को समाधान योजनाओं के जरिए बचाया है। इन योजनाओं के माध्यम से परिसमापन मूल्य की तुलना में **168.5% की वसूली** हुई है। IBC के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली समाधान प्राप्त फर्मों के प्रदर्शन में सुधार देखा गया है।
  - **कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सुधार** हुआ है। IBC के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्षों में इन्सॉल्वेंसी (दिवाला) मामलों को सुलझाने के तरीकों के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग 136 से 52 हो गई है।

2.1.7. बढ़ती अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय बाजारों का विकास (Evolving Financial Markets to Support the Investment Needs of a Growing Economy)

लचीला भारतीय वित्तीय बाजार

- **बाजार का बढ़ता आकार:** बाजार पूंजीकरण (Market capitalization) के मामले में भारतीय बाजार **दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है।** भारत का **सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाजार पूंजीकरण अनुपात** 2014 के 79% से बढ़कर 2022 में 104% हो गया था।
- **मजबूत संवृद्धि:** भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों (सेंसेक्स और निफ्टी 50) ने 2014-2023 के दौरान लगभग 13.5% की CAGR दर्ज की है। **MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में** भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है।
- **मजबूत संरचना:** निरंतर सुधारों के कारण भारतीय वित्तीय बाजार मजबूत बने हुए हैं। इन सुधारों में वित्तीय बाजारों का उदारीकरण और स्थिरता सुनिश्चित करने वाली विनियामक नीतियां शामिल हैं।
  - संरचना को मजबूत बनाने में **बैलेंस शीट क्लीन-अप और डिलीवरेजिंग (ऋण में कमी)** के परिणामस्वरूप ठोस कॉर्पोरेट बुनियादी फंडामेंटल्स से इसमें सहायता मिली है।

भारतीय वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन

- **खुदरा निवेशक:** डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने में वृद्धि के कारण खुदरा निवेशकों के लिए वित्तीय बाजारों तक पहुंच में आसानी हुई है।
- **IPO लिस्टिंग:** वित्त वर्ष 2015 के बाद से 1,050 कंपनियों ने संचयी रूप से **3.9 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई** है। इसके विपरीत, इससे पिछले 9 साल की अवधि में 441 कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपये ही जुटाए थे।
- **बॉण्ड बाजार:** संयुक्त राज्य अमेरिका के 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड और भारत के 10-वर्षीय सॉवरेन बॉण्ड यील्ड के बीच का अंतर 2016 तथा 2022 के बीच अपेक्षाकृत स्थिर रहा था। यह स्थिरता भारत के मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स को दर्शाती है।
  - **भारतीय कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार:** कंपनियां अब मुख्य रूप से बैंक ऋण पर निर्भर रहने की बजाय बॉण्ड जारी करके धन जुटा रही हैं।
    - **वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 2.9 गुना अधिक कॉरपोरेट बॉण्ड जारी** किए गए थे। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2023 के बीच **बकाया कॉरपोरेट बॉण्ड 12.8% की CAGR से बढ़े थे।**
    - **कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार** वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2030 (CRISIL रिपोर्ट) तक **दोगुने से अधिक** हो सकता है।

बॉण्ड बाजार को प्रोत्साहन

- **RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना** के जरिए आम निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों, जैसे- सॉवरेन बॉण्ड्स और गोल्ड बॉण्ड्स में सीधे निवेश कर सकते हैं।
- **सरकारी हरित परियोजनाओं** के निर्माण और संचालन के लिए, सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के माध्यम से **"सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड"** जारी किए हैं।
- सरकारी बॉण्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए **SEBI[21] ने InvITs और नगरपालिका बॉण्ड जैसे नए विकल्पों के लिए नियम** प्रस्तुत किए हैं। इससे बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण को अधिक दक्ष बनाया जा सकेगा।
- SEBI ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत **बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी वित्तीय जरूरतों का 25% ऋण प्रतिभूति जारी करके पूरा करना होगा।**
  - इस नियम के साथ कंपनी के **बॉण्ड में निवेश करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि को भी घटा** दिया गया है, ताकि अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

[21] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ Securities and Exchange Board of India

2.2. समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरता बनाए रखना (Safeguarding Macroeconomic Stability)

लचीले लक्ष्यीकरण (Flexible Targeting) के जरिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

- **वित्त वर्ष 2009 से 2014 के बीच की अवधि: औसत खुदरा मुद्रास्फीति 10% रही और समष्टि अर्थशास्त्रीय कमजोरियां** उजागर हुईं।
- **वित्तीय वर्ष 2016-2020:** वित्त वर्ष 2016 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के तहत **4 +/- 2%** के बैंड के साथ **लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया** गया था। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020 तक औसत खुदरा मुद्रास्फीति **4.2%** दर्ज की गई थी।
  - **मूल्य स्थिरीकरण निधि (2014-15)** ने महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी जिंसों में मूल्य अस्थिरता को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है।

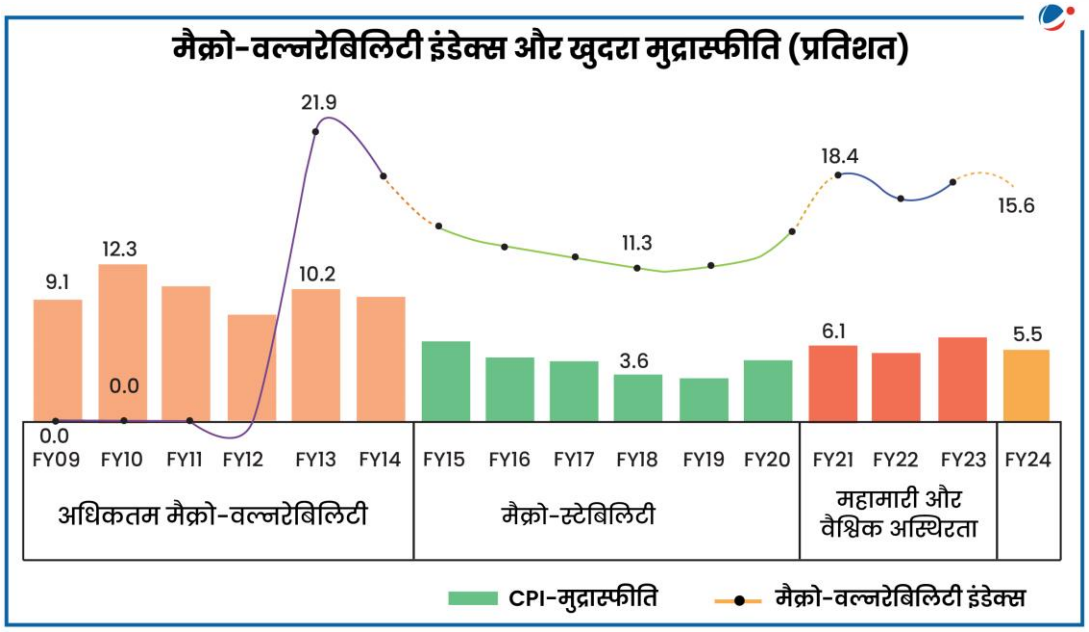

- **कोविड-19 महामारी की वजह से चुनौतियां (वित्त वर्ष 2021):** उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में व्यापक व्यवधानों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इससे राजकोषीय संतुलन बिगड़ गया था और आपूर्ति में बाधा के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई थीं।
  - वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया था। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें वित्त वर्ष 2021 में घट गई थी।
- **महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था (वित्त वर्ष 2022):** अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, संवृद्धि दर बढ़ी है और मुद्रास्फीति कम हुई है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 के अंत तक भू-राजनीतिक संघर्षों और संबंधित प्रतिबंधों के कारण **वैश्विक आर्थिक परिदृश्य फिर से खराब** हो गया था।
  - वैश्विक जिंसों की कीमतों और **कच्चे तेल की कीमतों** में उछाल आया है। इससे **भारत के बाह्य लेखे और मूल्य स्थिति (Price situation) प्रभावित** हुए हैं।

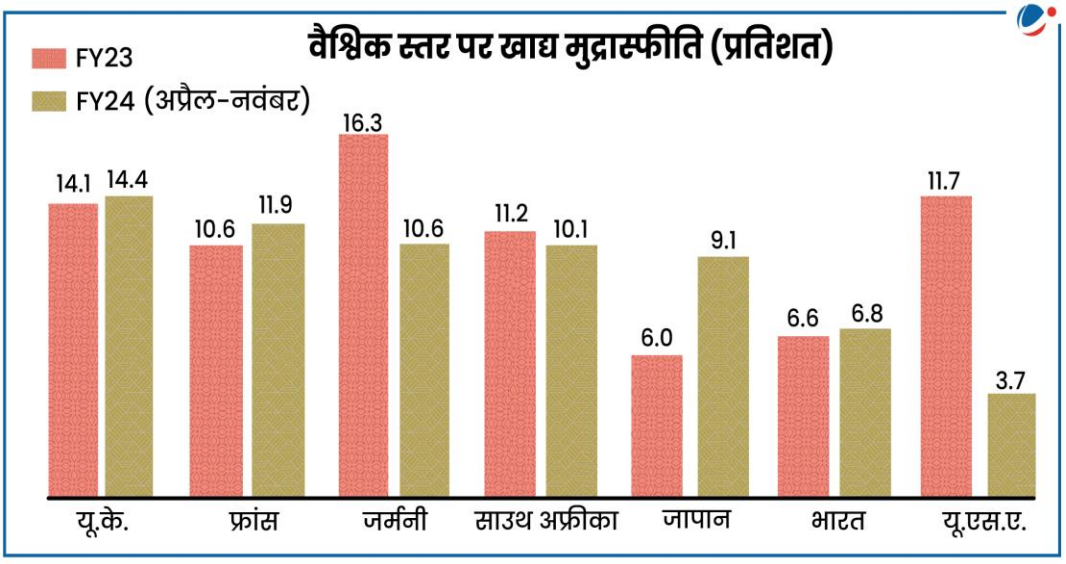

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और असमान मौसमी स्थितियों के कारण **सब्जियों की अधिक कीमतों ने खाद्य तेल की कीमतें बढ़ा दी थी।**

- **वित्त वर्ष 2023-24:** भारत कई अन्य देशों की तुलना में अपनी **खुदरा मुद्रास्फीति को कम स्तर पर रखने में सफल रहा है।** पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी आघातों से बचाने के लिए **तेल और प्राकृतिक गैस के आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने** का प्रयास किया है।
  - **वित्त वर्ष 2024 में औसत खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.5%** हो गई है। ऐसा कोर (गैर-खाद्य व गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण संभव हुआ है।
  - प्रमुख खाद्य पदार्थों के बफर को मजबूत करने और उन्हें समय-समय पर खुले बाजार में वितरित करने, व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय करने, स्टॉक सीमा के जरिए जमाखोरी को रोकने जैसे उपायों ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने में मदद की है।
  - **RBI की सहायक मौद्रिक नीति** ने यह सुनिश्चित किया है कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को समर्थन देते हुए लक्ष्य के अनुरूप रहे।

सरकार और RBI का लक्ष्य मजबूत उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थिरता तथा मजबूत बाह्य लेखे के साथ **समष्टि अर्थशास्त्रीय** स्थिरता वाला एक परिवेश बनाना है। सरकारी राजकोषीय संतुलन और बाह्य चालू खाता शेष में सुधार के साथ, मैक्रोइकोनॉमिक कमजोरियों में दोबारा कमी आने की संभावना है।

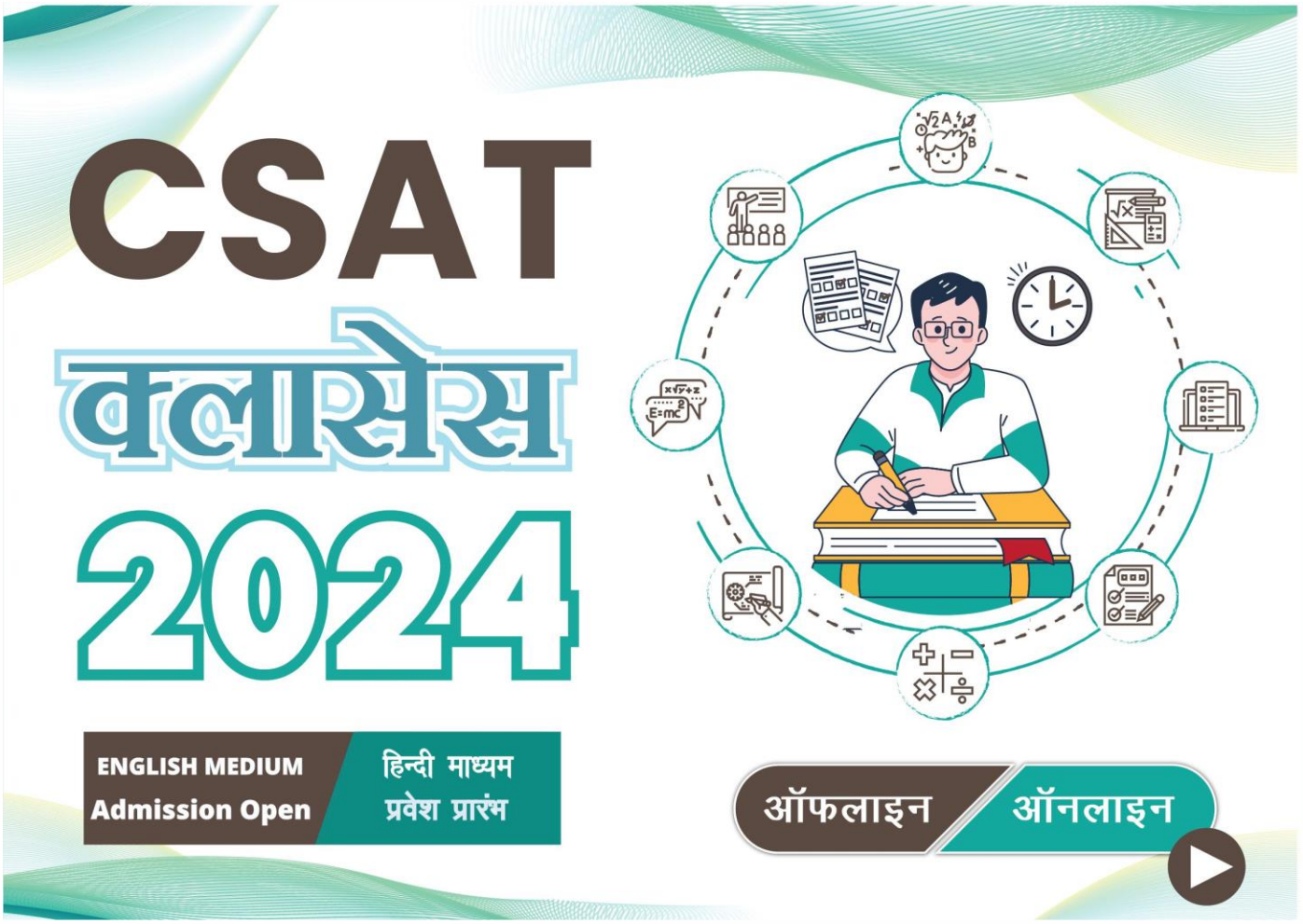

2.3. मानव संसाधन: कल्याण को सक्षम बनाने के साथ विकास को संतुलित करना (Human Resources: Dovetailing Growth with Capacitating Welfare)

2.3.1. वेलफेयर यानी कल्याण के प्रति एक नया दृष्टिकोण (A New Approach to Welfare)

- **वेलफेयर की भारतीय अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन** आया है, जो अब पहले की तुलना में **अधिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ, कुशल एवं सशक्त रूप लिए हुए** है।
- यह न केवल **सामाजिक अवसंरचनाओं** के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि **व्यक्तियों को अपने जीवन स्तर में सुधार करने** और उच्च संवृद्धि के साथ प्राप्त होने वाले अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
  - **वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2023 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय 5.9% की CAGR से बढ़ा है,** जबकि **सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 8.1% CAGR से बढ़ा** है।

मूलभूत सुविधाओं का सार्वभौमिकरण

- **कार्यकुशलता के साथ समानता:** बुनियादी सुविधाओं के सार्वभौमिकरण हेतु नीतियों में बदलाव किया गया है, लक्ष्य-आधारित एवं बजटीय आवंटन के लिए 'पैसा वसूल' तंत्र को लागू किया गया है। इसके अलावा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्त वर्ष 2020 से प्रमुख योजनाओं के लिए **आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को लागू** किया गया है।
  - **उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली** (MIS)[22] ने रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा** दिया है।
- **प्रमुख कार्यक्रम:** बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ रिसाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों को शुरू किया गया है, जैसे- DBT योजना, जन धन योजना-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, उज्ज्वला योजना, पी.एम.-आवास योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड आदि।

सामाजिक बदलाव के लिए निवेश

- टीकाकरण और स्वच्छता सेवाओं में निवेश करने से बीमारी के कम मामले जैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव सामने आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टीकाकरण और स्वच्छता सेवाओं में निवेश से स्वच्छ गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ती है एवं शरीर अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त करती है।
  - मिशन इंद्रधनुष के तहत 2014 से अब तक **5.1 करोड़ बच्चों और 1.3 करोड़ गर्भवती महिलाओं** का टीकाकरण किया जा चुका है।
  - **देश के 90% से अधिक गांव ODF प्लस** हैं, जबकि 100% गांवों को स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत 2019 में ही ODF घोषित किया जा चुका था।
- **सामाजिक सहायता: अटल पेंशन योजना, पी.एम. जीवन ज्योति योजना, पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना** (सभी योजनाएं 2015 में शुरू की गई हैं) आदि।

2.3.2. वेलफेयर के प्रति अपनाया गया नवीन दृष्टिकोण किस प्रकार लाभदायक रहा है (How has the new approach to welfare paid off)

- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच **13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी** से बाहर आ गए हैं। यह सकारात्मक प्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण भारत और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो **'अन्त्योदय' या अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सिद्धांत** के अनुरूप है।
- **NFHS (2019-21) के अनुसार,** बिजली, पीने के पानी, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन आदि तक पहुंच में लगातार सुधार हो रहा है।
  - **वित्त वर्ष 2015 में कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च का हिस्सा 62.6 फीसदी था, जो वित्त वर्ष 2020 में घटकर 47.1 फीसदी रह गया** था।
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)** 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर **2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म** हो गया है।
- वित्त वर्ष 2018 में **उच्चतर शिक्षा में महिला GER** ने पुरुष GER को पीछे छोड़ दिया है, आदि।

[22] Management Information Systems

नवीन कल्याणकारी दृष्टिकोण के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास

किफायती और संपूर्ण स्वास्थ्य	• आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लॉन्च के बाद से अब तक **30.3 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए** गए हैं। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 6.2 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। ○ 1.6 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** (तत्कालीन AB-HWCs) में अपग्रेड किया गया है। • नवंबर, 2023 तक **देशभर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले** जा चुके हैं। • वर्ष 2015 से 2022 के बीच **टी.बी. की घटनाओं में 16% की गिरावट** (मृत्यु दर में 18% की कमी) दर्ज की गई। • वित्त वर्ष 2022 में **जननी सुरक्षा योजना के 1 करोड़ लाभार्थी** थे।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार	• **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** लागू की गई। • आधारभूत चरण के लिए **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा**[23] के तहत, 2023 में लर्निंग टीचिंग मटेरियल (जादुई पिटारा) लॉन्च किया गया। • वर्ष 2023 में **परख**[24] आरंभ किया गया। • **निपुण भारत मिशन:** यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वह योजना है जिसके तहत कक्षा तीसरी के अंत तक सभी बच्चों को पढ़ना, लिखना और अंकगणित का ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना है। **समग्र शिक्षा के क्षेत्र में 2018-19 से 2023-24 तक की उपलब्धियां** • **3,000 से अधिक स्कूलों** को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड किया गया। ○ **235 नए आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले गए।** • **लड़कियों के लिए 28,000 से अधिक अलग शौचालयों** का निर्माण किया गया। • **ICT और डिजिटल पहल के अंतर्गत 1.2 लाख स्कूल कवर किए गए।**
बड़े पैमाने पर कौशल विकास	• 2015 से अब तक **1.4 करोड़ व्यक्तियों को पी.एम. कौशल विकास योजना** के तहत प्रशिक्षित किया गया है। • 2023 में **स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म** आरंभ किया गया था। यह एक अत्याधुनिक मंच है, जो कौशल संबंधी सभी पहलों को एक साथ लाता है। • **नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम** (सितंबर, 2023) के तहत **26.9 लाख प्रशिक्षुओं** को लाभ मिला है। • 2014 से 2022 तक **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना**[25] **के तहत 1.1 करोड़ व्यक्तियों को ITIs में दाखिला** प्रदान किया गया। • अप्रैल, 2018 से मार्च, 2023 के बीच **2 लाख लाभार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण**[26] प्रदान किया गया।
उद्यमशीलता (Entrepreneurship)	• **मुद्रा योजना** के तहत **26.1 लाख करोड़ रुपये** के ऋण स्वीकृत किए गए। • **पी.एम.-स्वनिधि** के लॉन्च होने के बाद से 58 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के **82.3 लाख ऋण स्वीकृत** किए गए हैं। • **स्टैंड-अप इंडिया** के तहत **2.1 लाख ऋण** स्वीकृत किए गए हैं (84% महिला उद्यमी)।

[23] National Curriculum Framework for Foundational Stage

[24] Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development: PARAKH/ समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण

[25] Craftsmen Training Scheme

[26] Entrepreneurship Training

मूलभूत सुविधाएं	• **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** 11 करोड़ शौचालय एवं 2.3 लाख सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण किया गया (जनवरी 2024)। • **जल जीवन मिशन:** 10.8 करोड़ घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया (जनवरी 2024)। • पिछले 9 वर्षों में पी.एम.-आवास (शहरी) के तहत 79 लाख घरों का निर्माण किया गया तथा पी.एम.-आवास (ग्रामीण) के तहत 2.5 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। • **पी.एम. उज्ज्वला योजना:** 2016 से 10 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। • **2015 से सौभाग्य योजना के तहत:** 21.4 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण (मार्च 2019) किया गया। • ग्रामीण क्षेत्रों में **4.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र** स्थापित किए गए (नवंबर 2023)।
सामाजिक सुरक्षा	• **पी.एम. जन धन योजना:** 51.4 करोड़ खाते खोले गए (जनवरी 2024)। • **पी.एम. जीवन ज्योति योजना** और **पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना** के तहत **क्रमशः 18.5 करोड़ और 41 करोड़** नामांकन (नवंबर 2023)। • **अटल पेंशन योजना:** दिसंबर 2023, सबस्क्राइबर्स की कुल संख्या बढ़कर 6.1 करोड़ हो गई, जो कि वित्त वर्ष 2015 के 20.7 लाख से 30 गुना अधिक है। • **पी.एम. श्रम योगी मानधन योजना:** दिसंबर 2023 तक 49.7 लाख असंगठित श्रमिक, इस योजना से जुड़ चुके हैं।

लोगों के कल्याण के प्रति अपनाया गया नवीन दृष्टिकोण कोविड-19 के "सदी में एक बार" संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में भी प्रकट हुआ। सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया ने **जोखिम के प्रति सुभेद वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने,** रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं के लिए **ऋण उपलब्ध करवाने** एवं घर वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए **रोजगार हासिल करने** आदि में मदद की।

2.3.3. महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास: 2047 तक लैंगिक लाभांश का दोहन (Women-led development: Tapping the Gender Dividend for India@100)

परिचय

महिला LFPR[27] 2017-18 में 23.3% था, जो 2022-23 में बढ़कर 37% हो गया। इसके अलावा, 2014-15 में जन्म के **समय लिंगानुपात 918** था, जो **2022-23 में बढ़कर 933 हो गया** है। **माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का GER** 75.5% (वित्त वर्ष 2015) से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 79.4% हो गया है।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण

- 2023 में **महिला आरक्षण विधेयक** {नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का पारित होना सरकार में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
  - महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व **बेहतर बाल स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा आउटकम्स** से भी जुड़ा हुआ है।
- 1991 में संविधान में संशोधन कर **स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया** गया था। वर्तमान में, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46% महिलाएं हैं।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

- **वित्तीय सेवाओं तक पहुंच:** पी.एम. जन धन योजना (PMJDY) ने भारत में ऐसी महिलाओं के अनुपात में वृद्धि की है जिनके पास बैंक खाता है एवं वे स्वयं उसका उपयोग करती हैं। 2015-16 में ऐसी महिलाएं 53% थी, जो 2019-21 में यह संख्या बढ़कर 78.6% हो गई।
- **महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs):** इनका **महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता** है।

[27] Labour Force Participation Rate/ श्रम बल भागीदारी दर

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM),** निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण, सामाजिक बुराइयों को कम करने, बेहतर शिक्षा, सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच आदि से जुड़ा हुआ है।
- DAY-NRLM (दिसंबर 2023) के तहत **9.5 करोड़ महिलाओं को 87.4 लाख SHGs से जोड़ा** गया है।
- हाल ही में, सरकार ने **SHGs सदस्यों को प्रशिक्षित करके उन्हें 'लखपति दीदी'** बनाने का लक्ष्य रखा है।

महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें एवं उनका प्रदर्शन

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP):** महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने से होती है। BBBP ने बालिकाओं को बचाने एवं उन्हें शिक्षित करने के प्रति सामूहिक चेतना को संवेदनशील बनाया है।
  - **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह बालिकाओं के लिए फंड जमा करने हेतु एक **लघु जमा योजना** है, जिसके तहत अब तक 3.1 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं।
- **पी.एम. मुद्रा योजना:** लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
- **स्टैंड-अप इंडिया:** 80% लाभार्थी महिलाएं हैं।
- **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA):** 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं (जुलाई 2023 तक)।
- **पी.एम. आवास योजना (ग्रामीण):** 2.4 करोड़ निर्मित आवासों में से 26.6% आवास पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं और 69% आवास संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर हैं।
  - संपत्ति का स्वामित्व घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी, छोटे बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य आउटकम्स और घरेलू हिंसा की कम घटनाओं से जुड़ा है।
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना:** जून 2022 तक **59 लाख से अधिक महिलाओं** (कुल का 40%) ने इस योजना के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

इन सभी पहलों का महिलाओं पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़ी चिंताओं का समाधान भी प्राप्त होता है। इसके अलावा, उत्पादक कार्यों के लिए समय और ऊर्जा की भी बचत होती है।

2.3.4. लंबी अवधि पर फोकस (Eyes on the long-term)

- **पोषण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण:** देश अभी भी **कुपोषण मुक्त भारत** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **कुपोषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।** इसे दूर करने के लिए **निरंतर और रणनीतिक प्रयास व संपूर्ण समाज आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता** है।
  - इस प्रकार, पोषण का क्षेत्र व्यापक हो गया है और अब इसमें स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, बुनियादी दवाएं, आवास और **जीवन चक्र दृष्टिकोण** को अपनाया जा रहा है।
    - **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी** और **पोषण 2.0** का लक्ष्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता के जरिए बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा में सुधार करना है।
  - **अब तक हासिल परिणाम:** इस दृष्टिकोण के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार-
    - 2015-16 से 2019-21 के बीच **बच्चों में ठिगनापन (Stunting) 38.4% से कम होकर 35.5% हो गया है** एवं **दुबलापन (Wasting) 21 प्रतिशत से घटकर 19.3% हो गया** है। इसके अलावा **कम वजन (Underweight) वाले बच्चों का प्रतिशत 35.8% से घटकर 32.1% हो गया** है।
- **शिक्षा का रूपांतरण:** इसके लिए नई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** को लाया गया है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी और नवीन शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य **शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना और महामारी के कारण पढ़ाई-लिखाई में हुए नुकसान की भरपाई करना** है।

2.3.5. पिछले दशक में रोजगार की स्थिति (Employment Situation in the Past Decade)

औपचारिकरण, कौशल विकास, उद्यमिता, उद्योग विविधीकरण और समावेशी विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भारत में रोजगार की स्थिति में **सकारात्मक बदलाव** आया है।

- NSO द्वारा प्रकाशित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[28] के अनुसार **2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी,** जो **2022-23 में घटकर 3.2% रह गई** है।
  - इसके साथ ही, ग्रामीण महिला LFPR में वृद्धि के कारण 2017-18 में LFPR 49.8% था, जो बढ़कर 2022-23 में 57.9% हो गया।
- वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2022 के बीच EPFO सदस्य संख्या में 11.3% CAGR की प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जो वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि का संकेत देता है।
- **नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2018 में 22.8% थी, जो **घटकर** वित्त वर्ष 2023 में 20.9% हो गई, लेकिन वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2023 के बीच नियमित वेतन वाली नौकरियों की कुल संख्या में लगभग 15 मिलियन की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, **नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि नौकरियों की कुल संख्या में गिरावट आई है।**
- नीति आयोग के अनुसार, **गिग इकोनॉमी ने वित्त वर्ष 2011 में 77 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान** किया। ऐसी सेवाओं की निरंतर उच्च मांग और नौकरी के लचीलेपन से टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रारंभिक स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है।

विद्यमान चुनौतियां

- **बढ़ते हुए कार्यबल को औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार हेतु सक्षम बनाना।**
- **उन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ाना जो कृषि से स्थानांतरित होने वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं।**
- नियमित वेतन/ वेतनभोगी रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए **सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ सुनिश्चित करना।**
  - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, **53% वेतनभोगी कर्मचारी किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।**

युवाओं के लिए रोजगार में वृद्धि

- **रोजगार में युवाओं (15-29 वर्ष के युवा) की भागीदारी में युवा आबादी के अनुरूप वृद्धि:** PLFS के अनुसार, युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% थी, जो घटकर 2022-23 में 10% हो गई है, जबकि युवा LFPR 38.2% से बढ़कर 44.5% हो गया है।
- **युवा कार्यबल भागीदारी दर 31% (2017-18) से बढ़कर 40.1% (2022-23) हो गई:** इसका मतलब है कि अतिरिक्त 35 मिलियन युवाओं को काम मिल गया है, भले ही युवाओं की आबादी में केवल 17 मिलियन की वृद्धि हुई है।

[28] Periodic Labour Force Surveys

- **युवाओं की आबादी में वृद्धि:** युवा आबादी में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश भी **युवा रोजगार में वृद्धि का नेतृत्व कर रहे हैं।**
  - उदाहरण के लिए- **उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर** 2017-18 में 16.7% थी, **जो 2022-23 में घटकर 7% रह गई है।**

महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि

- महिलाएं तेजी से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जो भविष्य में अधिक लाभ प्रदान करने वाले कार्यबल की भागीदारी को सक्षम बनाती है। इससे भारतीय संदर्भ में FLFPR और शिक्षा के बीच गोल्डिन के यू-कर्व हाइपोथेसिस को साकार किया जा सकता है।
  - **उच्चतर शिक्षा में महिला GER** वित्तीय वर्ष 2001 में 6.7% थी, जो वित्तीय वर्ष 2021 में **चार गुना बढ़कर** 27.9% हो गई, जबकि **उच्च माध्यमिक शिक्षा[29] में महिला GER** 2004-05 के 24.5% के मुकाबले 2021-22 में बढ़कर 58.2% हो गई है।

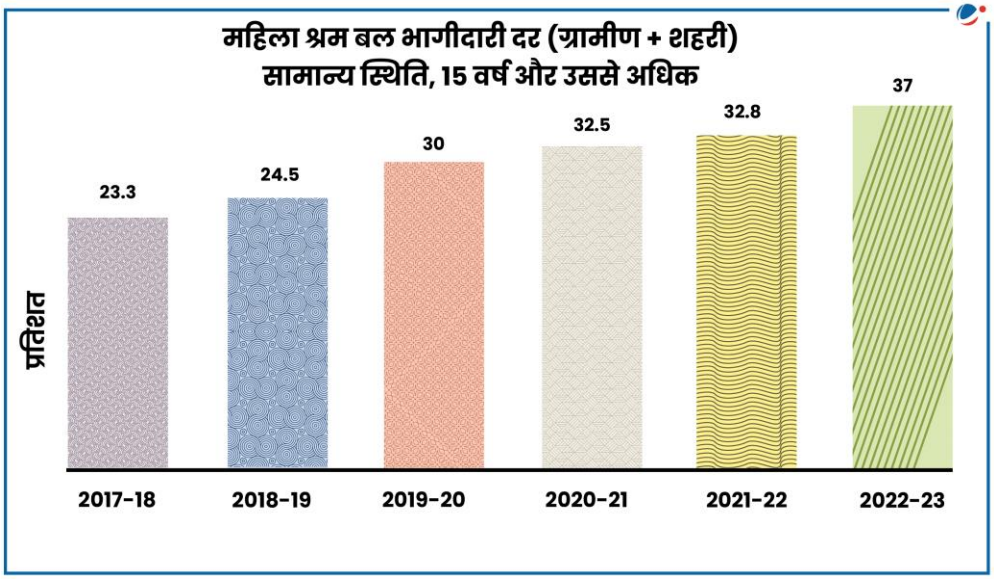

- FLFPR 2017-18 में 23.3% था, जो 2022-23 में बढ़कर 37% हो गया। इसके अलावा, शहरी FLFPR भी बढ़ रहा है एवं ग्रामीण FLFPR में तेज वृद्धि देखी गई है, जो स्व-रोज़गार और कृषि की हिस्सेदारी में वृद्धि से प्रेरित है।
  - ग्रामीण FLFPR में वृद्धि रोजगार श्रेणी और अवैतनिक सहायक श्रेणी दोनों में देखी गई है जो ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान का संकेत देती है।
- **एक ओर जहां कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ रही है वहीं पुरुष कार्यबल का झुकाव कृषि से दूर हो रहा है।**
  - वर्ष 2017-18 में कृषि में ग्रामीण महिला कार्यबल की हिस्सेदारी 73.2% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 76.2% हो गई। इसके विपरीत 2017-18 में कृषि में ग्रामीण पुरुष कार्यबल की हिस्सेदारी 55% थी, जो 2022-23 में घटकर 49.1% रह गई है।
- **कृषि का नारीकरण[30]**, कृषि के भीतर एक बहुत जरूरी संरचनात्मक बदलाव की ओर भी इशारा करता है, जहां अतिरिक्त श्रम (पुरुष) कृषि क्षेत्र से बाहर चला जाता है और शेष (महिला) श्रम का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है।
- **ग्रामीण पारिवारिक आय में महिलाओं का मौद्रिक योगदान अंतर-घरेलू सौदेबाजी की शक्ति और निर्णय लेने की दृष्टिकोण से भी मायने रखता है,** जो सामाजिक लैंगिक गतिशीलता में एक आमूलचूल बदलाव को प्रेरित करता है।

2.3.6. कौशल विकास और उद्यमिता (Skill Development and Entrepreneurship)

- **सरकार ने "आसानी से कौशल प्राप्त करना" सुनिश्चित करने एवं भारतीयों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं।** NEP, 2020 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी केंद्रित है।
  - PLFS 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार 15-59 वर्ष की आयु के 72.6% श्रमिकों को कोई औपचारिक/ अनौपचारिक व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिला है।
- **सरकारी प्रयासों** में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना (2014), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति और 2015 में कौशल भारत मिशन शामिल हैं।

[29] Senior secondary education

[30] Feminisation of agriculture

- सरकार ने हाल ही में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में **स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म** शुरू किया है।

- **परिणाम: वर्ल्ड-स्किल कम्पटीशन्स** में भारत की रैंक 2011 में 39 थी, जो 2022 में बढ़कर 11 हो गई है।
  - 2015 से अब तक लगभग 1.4 करोड़ लोगों को **पी.एम. कौशल विकास योजना** के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

2.4. भारत का बाह्य क्षेत्रक: अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित मार्ग तलाशना (India's External Sector: Safely Navigating Through Uncertainties)

2.4.1. वस्तु व्यापार में लचीलापन (Merchandise Trade Depicted Resilience)

- **निर्यात में हिस्सेदारी:** वित्त वर्ष 2004 के बाद से, **निर्यात बास्केट में प्रगतिशील तरीके से विविधीकरण** हुआ है। इसके अलावा, **GDP की तुलना में निवल निर्यात की हिसेदारी** भी बढ़ी है।
  - **वित्त वर्ष 2023 में 451.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वस्तु निर्यात दर्ज किया गया।**
- **सेवाओं का निर्यात:** सेवाओं के निर्यात में **लगभग आधी हिस्सेदारी सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात की** बनी हुई है।
  - वित्त वर्ष 2022 के बाद से **व्यावसायिक सेवाओं और वित्तीय सेवाओं दोनों ने ही दोहरे अंकों में निर्यात वृद्धि** दर्शाई है। यह सॉफ्टवेयर और समग्र सेवाओं के निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि के अनुरूप है।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय

- सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार विभिन्न नीतिगत और व्यापार सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित उपाय कर रही है।
  - MSME निर्यातकों के लिए नए बाजार तलाशने और उन्हें मौजूदा उत्पादों में विविधता लाने में सक्षम बनाने के लिए निर्यात लक्ष्यों का निर्धारण, निर्यात ऋण बीमा सेवाएं, निर्यात ऋण आदि से जुड़े उपाय किए गए हैं।
- दूरसंचार विभाग ने **अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। इसके तहत भारत में **कहीं से भी काम करने, अवसंरचनाओं को साझा करने**, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज (EPABX) के डिस्ट्रिब्यूटेड आर्किटेक्चर के उपयोग आदि की अनुमति दी गई है।
  - यह BPO और ITeS फर्मों को अपनी इनपुट लागत में कटौती करने में सक्षम बनाता है।

2.4.2. चालू खाते में सकारात्मक संतुलन (Comfortable Balance on Current Account)

- वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान **सेवा निर्यात (7.1% CAGR) और रेमिटेंसेस (4.5% CAGR)** ने भारत के चालू खाते के संतुलन को बेहतर स्थिति में लाया है, खासकर वित्त वर्ष 2014 के बाद की अवधि में।
- 2023 में भारत दुनिया में **रेमिटेंसेस** का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (125 बिलियन अमेरिकी डॉलर) देश रहा है।
- उच्च आय वाले देशों में नौकरी के लिए जाने वाले **भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी में संरचनात्मक बदलाव** आ रहा है। इन देशों में भारतीयों की भागीदारी कम कौशलयुक्त नौकरियों से उच्च कौशलयुक्त नौकरियों की ओर बढ़ रही है।
  - उदाहरण के लिए- वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, **भारत का 36% रेमिटेंसेस उच्च आय वाले गंतव्य देशों में कार्यरत उच्च कौशलयुक्त** और बड़े पैमाने पर उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों से प्राप्त होता है।
- **निजी अंतरण प्राप्तियां (Private transfer receipts)**, वित्त वर्ष 2023 में 26.2% की दर से बढ़कर **रिकॉर्ड 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गईं।** इसे वित्त वर्ष 2022 में 11.2% की सकारात्मक वृद्धि के कारण मदद मिली है।

2.4.3. पूंजी खाता (Capital Account)

- वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान **चालू खाते के नकारात्मक भुगतान संतुलन** की भरपाई पूंजी खाते के सकारात्मक अधिशेष से की जा रही है।
  - वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान **पूंजी खाते में 88.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि मुख्य रूप से भारत में विदेशी निवेश के उच्च प्रवाह के कारण** हुई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**
  - **स्थिति:** वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान, भारत को 596.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ था। यह इस अवधि के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के बराबर था। यूरोप में कोविड-19 महामारी के प्रभाव तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद, इस अवधि में भारत का FDI प्रवाह अधिक रहा है।
    - वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2014 के दौरान, भारत का कुल FDI प्रवाह 305.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% के बराबर था।
  - **FDI को आकर्षित करने वाले कारक:** कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रकों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दे दी गई है।
    - PLI योजना और मेक इन इंडिया जैसी नीतिगत पहलों से भारत में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिला है।
    - भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और समष्टि आर्थिक परिवेश में स्थिरता तथा वैश्विक निवेश के अनुकूल माहौल है।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)**
  - **स्थिति:** वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FPI अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया गया था।
    - वित्त वर्ष 2015 में पिछले दशक में FPI का सबसे अधिक अंतर्प्रवाह यानी 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था।
  - **FPI अंतर्प्रवाह को बढ़ावा देने वाले कारक:** रुपये की स्थिरता, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना आदि।

FPI के नियामक प्रणाली के सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए किए गए उपाय

- **FPIs को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट में भाग लेने,** REIT इकाइयों, INvITs, श्रेणी III के AIFs आदि में निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- **FPIs की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित** किया गया है तथा सेबी के साथ पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सामान्य आवेदन पत्र (CAF) की शुरुआत की गई है।
- **कुछ चिन्हित FPIs में** स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में **अतिरिक्त खुलासे करना अनिवार्य** किया गया है।

विनिमय दर

- **समष्टि आर्थिक स्थिरता और भारत की बाह्य स्थिरता में सुधार,** विशेष रूप से CAD में महत्वपूर्ण सुधार और सुरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार बफर के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारतीय रुपये में स्थिरता आई है।
  - वित्त वर्ष 2014 से 2023 के दौरान रुपया-डॉलर विनिमय दरें 60 रुपये प्रति डॉलर (USD) से 80 रुपये प्रति डॉलर की सीमा के बीच उतार-चढ़ाव करती रही हैं।

- मार्च 2023 से भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक के रूप में उभरा है।
- दिसंबर 2023 में **भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 623.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। यह दस महीने से अधिक की अवधि तक के आयात के लिए पर्याप्त था।
    - यह भंडार सितंबर 2023 के अंत तक **बाह्य ऋण (External Debt) के 98.1% हिस्से तक के लिए बफर** प्रदान करता है।

बाह्य ऋण

- **भारत का विदेशी ऋण:** सितंबर, 2023 में बाह्य ऋण 635.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस स्तर को अभी संतोषजनक माना गया है। **सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण** मार्च 2013 के 22.4% से कम होकर सितंबर 2023 में **18.6% हो गया।**
- **पिछले दशक के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP)[31] की स्थिति स्थिर रही:** कुल देनदारियां, जिसमें बड़े पैमाने पर गैर-निवासियों द्वारा किया गया निवेश शामिल है, में 6.5% (**वर्ष-दर-वर्ष**) की वृद्धि हुई है। जबकि सितंबर 2023 तक कुल संपत्तियों में 10.2% (**वर्ष-दर-वर्ष**) की वृद्धि हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर आरक्षित संपत्तियां शामिल हैं।

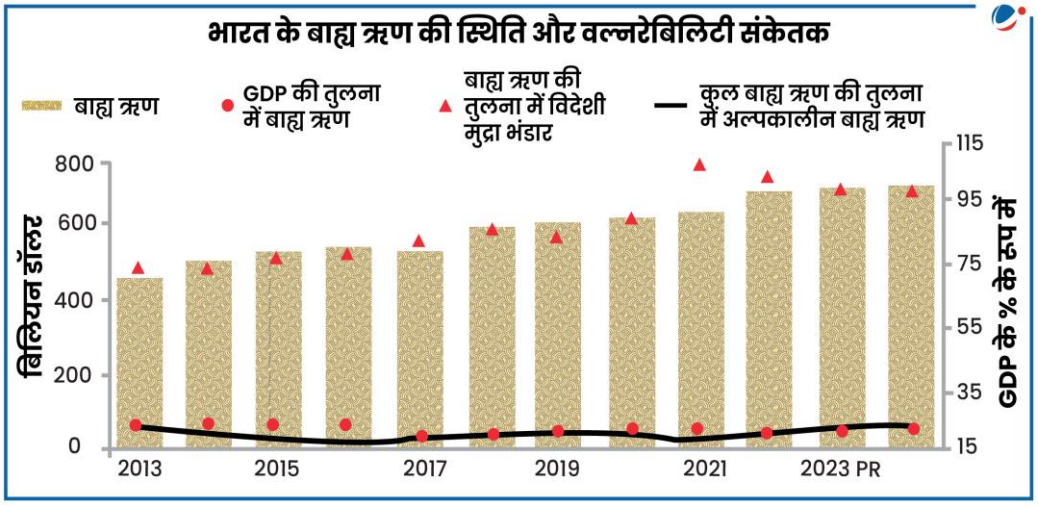

    - **IIP किसी देश की बाह्य वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की बैलेंस शीट** होती है।
    - **यह किसी देश के वित्तीय खुलेपन की मात्रा** का संकेतक है।
    - **NIIP भारत में गैर-निवासियों का शुद्ध दावा है जो किसी देश की साख को दर्शाता है।**

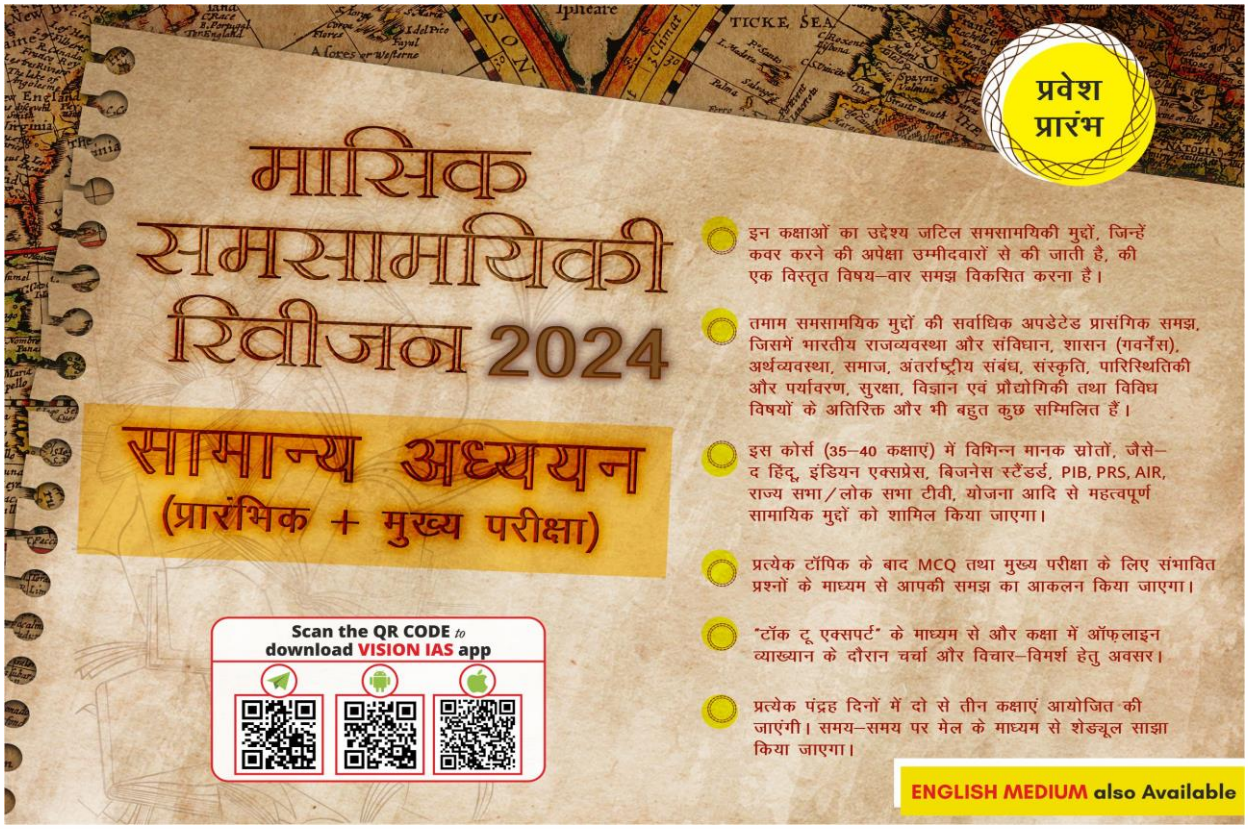

[31] International Investment Position

2.4.4. बाह्य क्षेत्रक के लिए आगे की राह (Way Ahead for External Sector)

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में कमी आने में अधिक समय लगना, धीमी संवृद्धि दर, भू-राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन में सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसी विभिन्न चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। हालांकि, FDI नीति में निरंतर सुधार, अवसंरचना को बढ़ावा और निवेश की सुविधा के कारण उम्मीद की गई है कि **भारत का बाह्य क्षेत्रक अनुकूल रहेगा।**

2.5. जलवायु कार्रवाई (Climate Action)

परिचय

सभी के लिए **संधारणीय और समावेशी आजीविका सुनिश्चित करते हुए अधिक अनुकूल विकास हासिल करना** देश की प्राथमिकता बनी हुई है। भारत आने वाले कुछ समय तक प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन वाला देश बना रहेगा।

2.5.1. अनुकूलनशीलता को बनाए रखने की दिशा में भारत की जलवायु कार्रवाई (India's Climate Action towards Building Resilience)

बहुपक्षीय जलवायु समझौतों में प्रावधान किए जाने के बावजूद, विकसित देश, विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए सहायता देने में पीछे रह जाते हैं। हालांकि, भारत अभी भी जलवायु कार्रवाई के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहा है।

- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)[32]:** भारत ने **2015 में UNFCCC में अपने पहले NDC की घोषणा** की थी। अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में **तीव्र प्रगति को देखते हुए 2022 में इसे संशोधित** किया गया।
  - **भारत में स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 9 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है।** यह मार्च 2014 के 80.3 गीगावाट से बढ़कर नवंबर 2023 में 187.06 गीगावाट हो गई।
  - भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 25 गुना से अधिक बढ़ गई है। यह मार्च 2014 के 2.63 गीगावॉट से बढ़कर नवंबर 2023 में 72.3 गीगावॉट हो गई।
    - **शुरू की गई योजनाएं:** सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।
      - ✓ रूफटॉप सोलर योजना, हरित ऊर्जा गलियारा।
      - ✓ 'उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल' के विनिर्माण के लिए PLI योजना शुरू की गई है।
      - ✓ PLI योजना 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज'।

NDC लक्ष्य - 2015	उपलब्धियां	संशोधित लक्ष्य (2022)
• भारत की **GDP की उत्सर्जन तीव्रता** को 2005 के स्तर से 2030 तक **33% से 35% तक कम करना**	• 2005 के स्तर से 2019 तक **अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी** हुई।	• GDP की **उत्सर्जन तीव्रता** में 2005 के स्तर से **45% की कमी** करना।
• 2030 तक **गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% स्थापित विद्युत क्षमता** का लक्ष्य प्राप्त करना।	• **गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता** नवंबर, 2023 में **43.9%** तक पहुंच गई। यह 2014 के 32.3% और 2004 के 30.4% से अधिक है।	• गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से 50% की **कुल विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य** प्राप्त करना।
• 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के जरिए **2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।**	• 2019 तक **1.97 बिलियन टन CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक** तैयार किया गया है, जो 2005 के स्तर से अधिक है।	• **LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली** के लिए एक जन आंदोलन के जरिए जीवन **जीने के स्वस्थ और संधारणीय तरीके** को बढ़ावा देना।

- **जलवायु परिवर्तन पर मजबूत राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** इसमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित नौ मिशन शामिल हैं - सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, संधारणीय कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय आवास, ग्रीन इंडिया, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान तथा हाल ही में शुरू किया गया स्वास्थ्य मिशन।

[32] Nationally Determined Contributions

- **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):** इसे जलवायु अनुकूलन कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2015-16 में शुरू किया गया है। इसके तहत 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि, जल, वानिकी, पशुधन आदि से संबंधित 30 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- **प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना:** इस ऊर्जा बचत आधारित बाजार तंत्र के परिणामस्वरूप लगभग 24.3 मिलियन टन तेल के समतुल्य ऊर्जा की बचत हुई है। इससे 2022 तक लगभग 105.02 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन से बचा जा सका।
- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया:** 2022 में घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए - कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) शुरू की गई है।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं:** प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम), सभी के लिए किफायती LED द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि।
  - उजाला के तहत 36.86 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं और SNLP के तहत 1.30 करोड़ से अधिक LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन:** GST की निम्न दरें, रियायती सीमा शुल्क, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक के तहत ऋण प्रदान करना आदि।
- **परिवहन क्षेत्रक में उपाय:** जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (FAME) योजना। भारत में कुल 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन हैं (दिसंबर 2023)।
  - **2017 की मेट्रो रेल नीति:** 2018-19 के बाद से देश में परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क का 450 कि.मी. से अधिक का विस्तार हुआ है। वर्तमान में, 900 कि.मी. से अधिक मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है।
    - मेट्रो रेल का विस्तार 2014 में 5 शहरों से बढ़कर 2023 में 20 शहरों तक हो गया है।
  - **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** इसे **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने** के लिए 2023 में लॉन्च किया गया था।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन और क्षमता निर्माण

- **समग्र रणनीति:** सरकार उच्च आर्थिक विकास हासिल करने, जीवन स्तर में सुधार करने, खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचनाओं में सुधार करने एवं जैव विविधता के संरक्षण आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, ताकि अनुकूलन बढ़ाया जा सके।
  - इसके लिए की गई पहलों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल भू-जल योजना, पी.एम. कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय तटीय मिशन, मिशन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 आदि शामिल हैं।
- वित्तीय अर्थव्यवस्था में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को मुख्यधारा में लाने के लिए **वित्तीय क्षेत्रक में अनुकूलनशीलता बढ़ाने की पहल** भी की गई है।
  - सेबी ने 2012 से शीर्ष **100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ESG से संबंधित प्रकटीकरण को अनिवार्य** कर दिया है।
  - **हरित ऋण प्रतिभूतियां** जारी करने के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है।
  - RBI द्वारा 'सॉवरेन ग्रीन बांड के लिए रूपरेखा', 'हरित जमा की स्वीकृति के लिए रूपरेखा' जारी की गई है।
  - **प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) नियमों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** को शामिल किया गया है।
  - शीर्ष कंपनियों द्वारा स्थिरता प्रभावों पर जानकारी सहित गैर-वित्तीय डेटा की रिपोर्टिंग की जाती है।
- **वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत के नेतृत्व में की गई पहलें:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2014), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, अनुकूल द्वीपीय राज्यों के लिए अवसंरचना, ग्रीन ग्रिड पहल- एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड आदि।
  - भारत स्वीडन के साथ मिलकर **लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन** (LeadIT) का सह-नेतृत्व भी कर रहा है। COP-28 में, नीतिगत फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के लिए दूसरे चरण के रूप में, LeadIT 2.0 लॉन्च किया गया था।

लक्ष्य को व्यावहारिकता के साथ संतुलित करना

- ऊर्जा सुरक्षा की अनदेखी करने वाली महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियां अल्पकालिक लागत को बढ़ावा देती हैं। यह लागत संभावित रूप से दीर्घकालिक लाभों से अधिक होती है।
  - ऊर्जा तक पहुंच हमारे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। यह उद्योगों को शक्ति प्रदान करती है तथा समग्र सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाती है। इसके साथ ही यह अधिकतम सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है।
- जलवायु नीति के लाभों से जुड़ी अनिश्चितताएं उनकी लागत से जुड़ी अनिश्चितताओं से अधिक है। **दुर्लभ खनिजों, वैकल्पिक हरित प्रौद्योगिकियों तथा पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए आवश्यक रियायती वित्त तक सीमित पहुंच** से अनिश्चितताओं में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार को पारंपरिक कार की तुलना में छह गुना अधिक खनिज आधारित आगतों की आवश्यकता होती है। खनिजों की आवश्यकता में वृद्धि का अर्थ है ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि।

विकास: एक पूर्व शर्त के रूप में

- **विकास प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधन और क्षमता में वृद्धि करता है;** इस प्रकार यह अनुकूलन में वृद्धि करने और प्रभावी शमन कार्रवाई को सक्षम करने में महत्वपूर्ण है।
  - हालांकि, जलवायु परिवर्तन के प्रति वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहा है जिससे कई देशों की निम्न-आय की स्थिति का स्थायी बने रहने का जोखिम बना हुआ है।
- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ मिश्रित निकट अवधि की व्यावहारिकता,** ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की नीतियों को आकार दे रही है।
- **2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने और 2030 के लिए NDC लक्ष्यों को प्राप्त** करने की दिशा में बढ़ने के लिए व्यापक नीति और विनियामकीय उपायों को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही असंतुलित और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और सूझबूझ के साथ उपयोग के साथ उत्पादन करने और उपभोग पैटर्न को सुधारने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  - भारत जलवायु कार्रवाई के नेतृत्वकर्ता रूप में और **जलवायु कार्रवाई में अपने उचित योगदान की तुलना में 2°C तक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने वाला G-20 समूह का एकमात्र राष्ट्र है।**

2.6. आउटलुक (Outlook)

वर्तमान में, कोरोना महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव, व्यापक भुगतान असंतुलन और कमजोर वित्तीय क्षेत्रक वाली अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद, भारत 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (अनुमानित वित्तीय वर्ष 2024) की GDP के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक GDP ग्रोथ रेट 7% के करीब रहने की संभावना है। **2030 तक ग्रोथ रेट 7% से ऊपर जाने की संभावना** भी काफी अधिक है।

केवल **भू-राजनीतिक संघर्षों का जोखिम** ही चिंता का विषय है। भविष्य के सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कौशल, लर्निंग आउटकम्स, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, MSME के लिए अनुपालन संबंधी बोझ में कमी और श्रम बल में लैंगिक संतुलन शामिल हैं।

अगले 3 वर्षों में, भारत के **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने** की उम्मीद है। तार्किक अनुमानों के तहत, भारत अगले 6-7 वर्षों में (2030 तक) 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है। हालांकि, सरकार ने **2047 तक "विकसित देश" बनने** का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है।

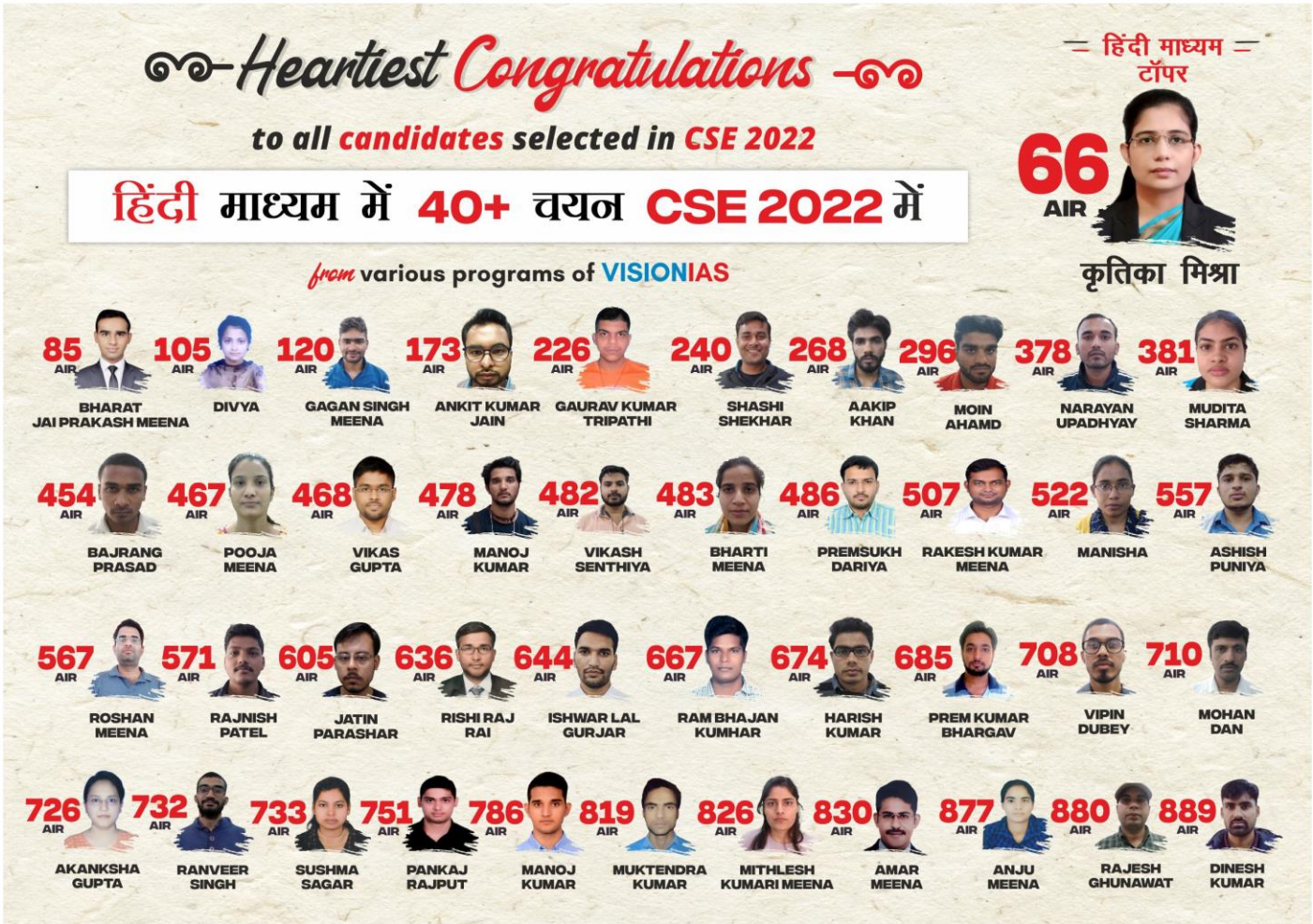

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

t.me/hindi_visionias

vision_ias_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

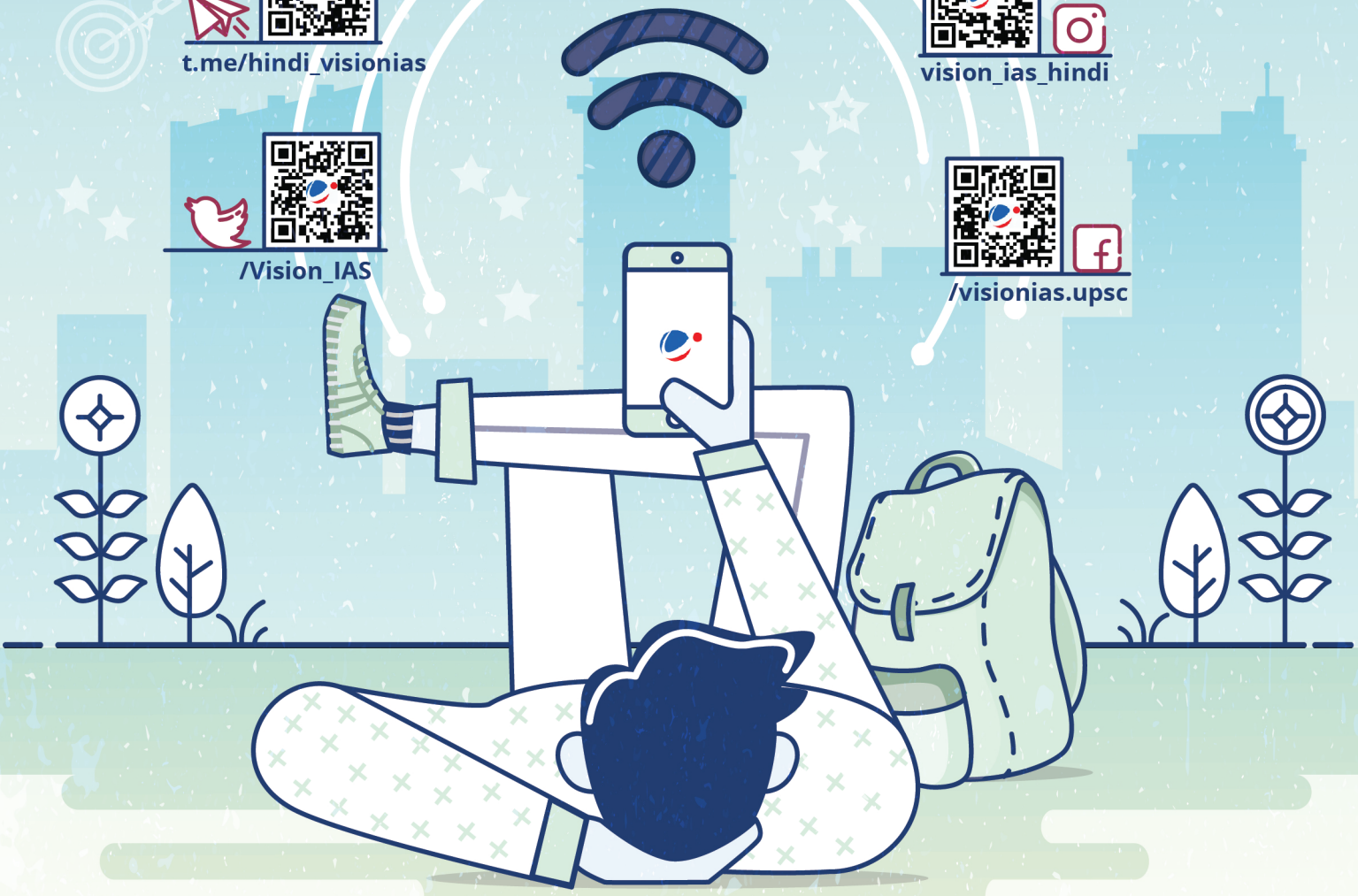

www.visionias.in

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

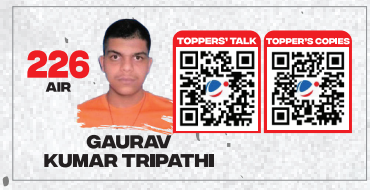

CSAT MATH 7 YEARS PYQ

सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें

GS 7 YEARS PYQ

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

Mukherjee Nagar Centre
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर